● वर्ष-3
● अंक-72
रायपुर, गुरुवार
02 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

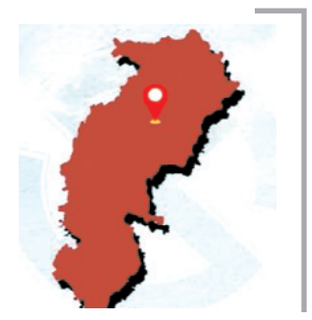

पेज-6›› कटघोरा सामान्य सीट पर ...

मध्य प्रदेश में चुनावी खेल बिगाड़ेंगे बागी

भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के लिए बगावत सबसे ज्यादा सिरदर्द बना हुआ

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर है। हालांकि, दोनों बड़ी पार्टियों के लिए बगावत सबसे ज्यादा सिरदर्द बना हुआ है। प्रदेश सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाह इस बार निवाड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां बड़ी हैं। टिकट नहीं मिलने पर आमिर अकिल, जीतेंद्र डागा, कमलेश्वर देवलिया, केके श्रीवास्तव, कमलेश अग्रवाल, शैलेन्द्र चौधरी, जयकांत सिंह, राजेंद्र सिंह सोलंकी, कौशल्या गोटिया समेत कई नेता नाराज हैं। अपने इलाके में दबदबा रखने वाले इन नेताओं की एंट्री से आलाकमान चिंतित है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश संगठन महासचिव हितानंद शर्मा बीजेपी में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं से बात कर रहे हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव और अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी मनाने में लगे हुए हैं। वहीं, अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से बगावत करने वाले नेताओं से बातचीत

करने में जुटे हैं।

भाजपा के बागी

पूर्व सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन बुरहानपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। डेढ़ साल पहले खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद लोकसभा उपचुनाव में बेटे हर्ष वर्धन टिकट के दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा था। इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को टिकट दिया।

पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर पृथ्वीपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले नंदराम कुशवाह 2021 विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। नंदराम इस चुनाव में निवाड़ी विधानसभा से बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। यहां पार्टी ने दो बार के विधायक अनिल जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब राज्य मंत्री नंदराम कुशवाह निवाड़ी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

केके श्रीवास्तव भी बागी हो गये हैं। वह 2013 से 2018 तक विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर राकेश गिरी को दे दिया था। वे विधायक चुने गये। इस बार फिर केके श्रीवास्तव दावेदारी कर रहे थे, जबकि बीजेपी ने राकेश गिरी को मैदान में उतारा है। ऐसे में केके श्रीवास्तव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि, उन्हें मनाने की कोशिश हुई।

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने पार्टी से बगावत कर दी है। वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर मध्य विधानसभा से कमलेश अग्रवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनका आरोप है कि बाहरी उम्मीदवारों को लाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। बीजेपी ने अभिलाष पांडे को मैदान में उतारा है जबकि कांग्रेस ने विनय सक्सेना को मैदान में उतारा है।

कांग्रेस के बागी

भोपाल उत्तर विधानसभा सीट पर 6 बार के कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के भाई आमिर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। आमिर अपने बड़े भाई की सीट पर टिकट मांग रहे थे। हालांकि, कांग्रेस ने आरिफ अकील के बेटे आतिफ को मैदान में उतारा है। इससे नाराज होकर आमिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। नरसिंहपुर की गोटेगांव सीट से पूर्व विधायक जितेंद्र डागा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। डागा कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने पिछला चुनाव हारे नरेश ज्ञानचंदानी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

जबलपुर की बरगी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सोबरन सिंह के बेटे जयकांत सिंह ने बगावत कर दी है। दो बार के कांग्रेस विधायक सोबरन सिंह के बेटे जयकांत सिंह ने 2018 में भी बरगी विधानसभा से टिकट मांगा था। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2023 में उन्हें टिकट जरूर मिलेगा। जयकांत सिंह का कहना है कि उनके पिता ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, फिर भी उनकी उपेक्षा की गई।

बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मुरली मोरवाल का टिकट काटकर राजेंद्र सिंह सोलंकी को दे दिया था। भोपाल में मोरवाल के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद राजेंद्र सिंह सोलंकी का टिकट बदलकर दोबारा मुरली मोरवाल को दे दिया गया।

मराठा आरक्षण: कुनबी जाति प्रमाणपत्रों का वितरण आरंभ

नईदिल्ली। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बुधवार को राज्य के धाराशिव जिले के अधिकारियों ने मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों को कुनबी जाति के प्रमाण पत्र वितरित करने शुरू किए, जिसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल होने का उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह का पहला प्रमाण पत्र सबूत के आधार पर जिले के कारी गांव के सुमित माने को सौंपा गया। जिलाधिकारी सचिन ओम्बासे ने माने को कुनबी जाति प्रमाण पत्र सौंपा। इससे एक दिन पहले राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें संबंधित अधिकारियों से मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया है ताकि उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

ओम्बासे ने कहा, सरकार के निर्णय के अनुसार, हमारे जिले में कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभिलेखों के अनुसार, हमने आज पहला कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी किया है। हम शेष लाभार्थियों की पहचान करके उन्हें प्रमाणपत्र सौंपेगे। उन्होंने कहा, हम अगले 8-10 दिन में (आवेदकों को) ये प्रमाणपत्र जारी करने के इच्छुक हैं। राजस्व विभाग की एक टीम आवेदकों से संपर्क करेगी और उन्हें प्रमाणपत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा

कि जो रिकॉर्ड मिलते हैं उन्हें हमारी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर प्रमाणित प्रतियों के रूप में अपलोड किया जाता है। अधिकारी ने कहा, शेष दस्तावेज अगले कुछ दिनों में अपलोड कर दिए जाएंगे। लोगों को उचित दस्तावेजों, पते के प्रमाण और परिवार के इतिहास के साथ ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।

महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले महीने फैसला किया था कि मराठवाड़ा क्षेत्र के उन मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे जिनके पास निजाम युग के ऐसे राजस्व या शिक्षा दस्तावेज हैं जिनके जरिए कुनबी के तौर पर उनकी पहचान होती हो। कृषि से जुड़ा समुदाय कुनबी समुदाय महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है। माने को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, धाराशिव के जिलाधिकारी ओम्बासे ने कहा, कुनबी मुद्दे पर गठित समिति ने मराठवाड़ा के हर जिले का दौरा किया।

पीएम मोदी आज पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स से मिले। ये मुलाकात बुधवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम में हुई। जहां एथलीट्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था। इसमें पीएम मोदी के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे।

पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी, फिर दूसरों की बारी: चड्ढा

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेशी से एक दिन पहले, आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में छूट पाने के लिए विपक्ष शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने की योजना तैयार की है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चड्ढा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां ??पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगी और फिर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन सहित अन्य मुख्यमंत्रियों के पीछे जाएंगी। आप नेता ने कहा कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है। इसके साथ ही वे अगली गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की करेंगे। अगली गिरफ्तारी राजद नेता तेजस्वी यादव की हो सकती है, ताकि राजद बिहार में चुनाव लड़ने में सक्षम न रह जाए। इसके बाद बीजेपी एजेंसियों की अगली एंट्री जिस राज्य में होगी वो है पश्चिम बंगाल। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए सभी मामलों में से 95 फीसदी मामले बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हैं। उन्होंने मनीष सिसौदिया, राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला समेत सभी बड़े नेताओं के खिलाफ

मामले दर्ज किए हैं।

चड्ढा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सामने आने के बाद बीजेपी को समझ आ गया कि वे इस संयुक्त मोर्चे के खिलाफ जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, इस प्रकार भाजपा ने इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना तैयार की। जब शीर्ष नेता जेल में होंगे, तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि वे अदालती मामलों में व्यस्त होंगे। राज्यसभा सांसद ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी सात संसदीय सीटें जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष विपक्षी नेताओं के पीछे जाकर उन्हें गिरफ्तार करेगी। चड्ढा ने कहा कि भाजपा राज्य और संसदीय चुनावों में खुली छूट चाहती है और दावा किया कि भाजपा राज्य में एक पार्टी का एकाधिकार चाहती है।राष्ट्रीय राजधानी में खराब वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि 1 नवंबर से अगले 15-20 दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में महत्वपूर्ण होंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई थी। वहीं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 1 नवंबर से अगले 15 से 20 दिन अहम हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तापमान गिर रहा है और हवा की गति कम हो गई है, इसलिए प्रदूषक तत्व निचले स्तर पर हैं। कल, त्क्ष्ठ करीब 350 था। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट पर चल रहे काम की वजह से स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है।

प्रमुख समाचार

ईडी ने जेट एयरवेज, गोयल परिवार की संपत्ति कुर्क की

नईदिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जेट एयरवेज और नरेश गोयल परिवार से जुड़ी ?538.05 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। एजेंसी ने नरेश

गोयल सहित कई कंपनियों और व्यक्तियों से संबंधित 17 आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों को जब्त कर लिया है। उनकी पत्नी अनीता गोयल और बेटा निवान गोयल। ये संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर 17 आवासीय फ्लैट/बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने केनरा बैंक की लिखित शिकायत के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने जेआईएल और उसके प्रमोटरों और निदेशकों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया था। एजेंसी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला है कि जेआईएल ने एसबीआई और पीएनबी के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ द्वारा दिए गए।

महुआ के कैश-फॉर-क्वेरी के आरोप 2005 से गंभीर: दुबे

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर ताजा हमला बोला और दावा किया कि उनके खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी के आरोप 2005

के कैश-फॉर-क्वेरी घोटाला मामले से कहीं अधिक गंभीर हैं, जिसमें 11 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि संसद में 10,000 रुपये के लिए सवाल पूछने पर सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। यह (मोइत्रा का मामला) उससे कहीं अधिक गंभीर मामला है। इस मामले पर मोइत्रा को लोकसभा आचार समिति के समन के बारे में पूछे जाने पर, दुबे ने यह कहते हुए जवाब देने से परहेज किया कि नियमों के अनुसार, उस मामले पर बोलना अनुचित होगा जिसकी जांच पहले से ही पैनल द्वारा की जा रही है। वर्ष 2005 में छत्रपाल सिंह लोढ़ा (भाजपा), अन्ना साहेब एम के पाटिल (भाजपा), मनोज कुमार (राजद), चंद्र प्रताप सिंह (भाजपा), राम सेवक सिंह (कांग्रेस), नरेंद्र कुमार कुशवाहा (बसपा), प्रदीप गांधी (भाजपा), सुरेश चंदेल (भाजपा), लाल चंद्र कोल (बसपा), वाईजी महाजन (भाजपा), और राजा रामपाल (बसपा) पर संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।

तेलंगाना के लोगों से लूटा गया पैसा लौटाने की प्रतिज्ञा

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को एक चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के लोगों से एक महत्वपूर्ण वादा किया। उन्होंने तेलंगाना के लोगों से लूटा गया पैसा उन्हें

लौटाने की प्रतिज्ञा की। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए, गांधी ने घोषणा की, मैं पीएम नरेंद्र मोदी नहीं हूं। जब मैं कुछ वादा करता हूं, तो मैं उसे पूरा करता हूं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) पर हमला बोलते हुए गांधी ने कहा कि सबसे पहले वह मुख्यमंत्री पद को अलविदा कहेंगे। फिर, हम केसीआर द्वारा तेलंगाना के लोगों से लूटे गए पैसे के बारे में सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी ने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैंने मन बना लिया है कि ष्टरूने जो पैसा लूटा है, वह कांग्रेस वापस आपकी जेब में डालेगी। मैं पीएम मोदी नहीं हूं, जब मैं कोई वादा करता हूं तो उसे पूरा भी करता हूं। उन्होंने कहा कि हम सबने तेलंगाना का सपना देखा था और सोचा था कि तेलंगाना की जनता इस राज्य पर राज करेगी। पिछले 10 साल से तेलंगाना की जनता को परे कर दिया गया है और एक राजा और उसका परिवार तेलंगाना पर राज कर रहा है।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 12 फीसदी की वृद्धि

नईदिल्ली।2022 में भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों (9.4 प्रतिशत) और चोटों (15.3 प्रतिशत) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, दिल्ली के बाद बेंगलुरु में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की दूसरी सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में बेंगलुरु की संकरी सड़कों पर 3,822 दुर्घटनाओं में 772 लोगों की जान चली गई, जबकि 2021 में 654 सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुईं। इसके अलावा, 3,189 बेंगलुरुवासी घायल हुए हैं। शहर की सड़कें, जो आमतौर पर अपनी ख़राब हालत के लिए सुर्खियाँ बनती हैं। इस बीच, चेन्नई में मृत्यु दर में उल्लेखनीय 49 प्रतिशत की कमी देखी गई, 2021 में 998 की तुलना में 2022 में 507 सड़क मौतें हुईं। हालांकि, तमिलनाडु में 2022 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिसमें कुल 64,105 मामले थे। पूरे भारत में, 2022 में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 1,68,491 मौतें हुईं और 4,43,366 घायल हुए।

एआईएमआईएम नेता ने किया जिलाबदर आदेश का उल्लंघन

नईदिल्ली।ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की ओर से दो दिन पहले इंदौर-1 विधानसभा सीट से पर्चा भरने वाले 40 वर्षीय उम्मीदवार को जिलाबदर किए जाने के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। इंदौर से करीब 130 किलोमीटर दूर खरगोन कस्बे में पिछले साल रामनवमी पर हुए सांप्रदायिक दंगों के आरोपियों में शामिल एआईएमआईएम नेता का दावा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश'' के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, यासिर पठान के आपराधिक गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल रहने के कारण खरगोन के प्रशासन ने 13 मार्च को आदेश जारी किया था कि वह खरगोन के साथ ही इंदौर और आस-पास के अन्य जिलों की राजस्व सीमाओं में साल भर तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे।अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह ने बताया,''पठान इंदौर के खजराना क्षेत्र में 30 अक्टूबर को घूमते पाए गए और जिलाबदर के आदेश के उल्लंघन के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।'' सिंह ने बताया कि पठान के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और तय कानूनी प्रक्रियाओं के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत

नईदिल्ली। भारत कई क्षेत्रों में जबर्दस्त प्रगति का साक्षी रहा है, जिसमें डिजिटलीकरण, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना, विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने की खातिर बेहतर नीतिगत माहौल और बुनियादी ढांचे पर खर्च में भारी वृद्धि शामिल है। नीतियों की निरंतरता के कारण भारत के सकारात्मक विकास के लिए आधार तैयार किए गए हैं।

वित्त वर्ष-24 की पहली तिमाही में 7.8 फीसदी की वृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस वृद्धि को मजबूत खपत, बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट क्षेत्रों में चल रहे निवेश, सेवा निर्यात में निरंतर वृद्धि, एक संपन्न सेवा क्षेत्र, सकारात्मक उपभोक्ता और व्यावसायिक विकास का समर्थन हासिल है। रिजर्व बैंक के ताजा अनुमानों में वित्त वर्ष-2024 में भारत के लिए 6.5 फीसदी और वित्त वर्ष 2025 में 6.2 फीसदी की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कई नीतिगत सुधार और समर्थन, सरकार द्वारा विशाल पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किए जाने, मजबूत कॉरपोरेट एवं बैंक बैलेंस-शीट ने (जिनमें एनपीए पर काबू पा लिया गया है) आने वाले लंबे समय के लिए निरंतर आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

वर्ष 2014 में वैश्विक जीडीपी के मामले में दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा भारत अब पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी सुधार हुआ है और वर्ष 2014 के 147वें पायदान से ऊपर उठकर अब यह 127वें पायदान पर आ गया है। इस दौरान जीएसटी, आईबीसी, जनधन, आधार, यूपीआई और पीएलआई योजनाएं जैसे ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। मुद्रास्फीति पर भी उल्लेखनीय नियंत्रण हुआ है। ऐसा एमएसपी में कम वृद्धि, सौभाग्य से कच्चे तेल/वस्तु की कीमतों में कमी और कोविड के दौरान विवेकपूर्ण उपायों से हुआ है। इसके अलावा, व्यावसायिक सुगमता सूचकांक में भारी उछाल के साथ कारोबारी धारणा में सुधार हुआ है। और अब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

बुनियादी ढांचों के विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अपना निवेश बढ़ाया है। पिछले नौ वर्षों में राजमार्गों में लगभग 60 फीसदी की वृद्धि हुई है और रेलवे के बुनियादी ढांचे में निवेश चार गुना से अधिक बढ़ गया है। बंदरगाहों की क्षमता में 83 फीसदी की वृद्धि हुई है। मेट्रो लाइन की लंबाई साढ़े तीन गुना बढ़ी है, जिससे और अधिक शहर मेट्रो रेल लाइन से जुड़ गए हैं। उड़ान योजना के तहत 73 नए हवाई अड्डों के संचालन का काम हुआ है। वित्तीय समावेशन और डिजिटाइजेशन के मोर्चे पर भी भारी सफलता मिली है।

वर्ष 2014 के बाद से खोले गए 50 करोड़ जन-धन खातों की बदौलत वर्ष 2023 में 80 फीसदी से ज्यादा लोगों के बैंक खाते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वर्ष 2014 में 7,400 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर सात लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार ने सब्सिडी देने के लिए जन धन-आधार-मोबाइल-पैन का प्रभावी ढंग से उपयोग करके विलंब और बिचौलियों को खत्म कर दिया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने भी जबर्दस्त प्रगति की है। ऑटोमोबाइल की बिक्री में वृद्धि, बिजली की बढ़ती मांग, ई-वे बिल की मात्रा, पैसेंजर ट्रैफिक में वृद्धि, घरेलू क्षेत्र में बैंक ऋण के प्रवाह में उच्च वृद्धि और ग्रामीण मांग वृद्धि में सुधार बढ़ते उपभोग का संकेत देते हैं। बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट क्षेत्र फल-फूल रहे हैं, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि, सीमेंट, स्टील की खपत और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च में परिलक्षित होता है।

जीडीपी प्रतिशत के रूप में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भी वृद्धि हुई है। हालांकि समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र की कम वृद्धि, माल के निर्यात और आयात में संकुचन, और अर्थव्यवस्था में एफडीआई, वेंचर कैपिटल (वीसी) और प्राइवेट इक्विटी (पीई) फंड के निचले स्तर के साथ-साथ कच्चे तेल और थोक बिजली की कीमतों में वृद्धि से कुछ चिंताएं पैदा होती हैं।जीएसटी संग्रह ने अब तक जीडीपी वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में प्रत्यक्ष कर संग्रह मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन का संकेत है। मजबूत मांग की स्थिति के बीच नए कारोबार में तेज वृद्धि के कारण सितंबर में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, और समग्र व्यापार माहौल में सुधार के कारण नौकरियों की संख्या में वृद्धि जारी रही। नवीनतम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) का परिणाम भारत के सेवा क्षेत्र की सकारात्मक खबर लेकर आया, सितंबर में व्यावसायिक गतिविधि और नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश में 13 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई।

कोंडागांव जिले में मतदान की तैयारियां पूरी, आदर्श और पिंक बूथ से मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होना है। पहले फेज के लिए 20 विधानसभा सीटों में 7 नवंबर को मतदान होगा। बस्तर और दुर्ग संभाग में 7 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे। 7 नवंबर को पहले फेज के मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर कोंडागांव ने मीडिया से खास बातचीत की है।

जिले मतदान की तैयारी की गई पूरी

जिला निर्वाचन अधिकारी और कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि कोंडागांव जिले के दो विधानसभा कोंडागांव और केशकाल के साथ नारायणपुर विधानसभा का कुछ क्षेत्र कोंडागांव जिले में आता है। कोंडागांव जिले में निर्वाचन आयोग के टाइम टेबल के मुताबिक 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए जिले में पूरी तैयारी कर ली गई है।

संवेदनशील जगहों पर बूथ स्थापित

कलेक्टर के मुताबिक जिले में कुल 588 मतदान केंद्र हैं। पहले जिले में 550 मतदान केंद्र थे। अब 38 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। जो पहले संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। इन जगहों पर पहले 10 या 12 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। लेकिन अब उनके गांव में ही अब मतदान के लिए सुविधा दी गई है। पोलिंग बूथ स्थापित कर दिए गए हैं। संवेदनशील बूथों में वॉल राइटिंग कंप्लीट कर ली गई है। 7 नवंबर की डेट सभी

को बताई गई है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।

विधानसभा में बनाए गए आदर्श और पिंक बूथ

प्रत्येक विधानसभा में 10 पिंक बूथ बनाए गए हैं।जो पूरी तरह से महिलाएं ही संचालित किए जाएंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए भी एक बूथ बनाया गया है।जिसमें सभी दिव्यांगजन कर्मी होंगे।वहीं युवाओं को मतदाने में हिस्सा लेने के लिए युवा बूथ भी बनाए गए हैं। विधानसभा में कुल 12 स्पेशल बूथ भी होंगे। जिन्हें आदर्श बूथ नाम दिया गया है।

आचार संहिता का पालन करवाने के लिए टीम गठित

समय-समय पर पॉलीटिकल पार्टियों की मीटिंग करके उनको भी आदर्श आचार संहिता के बारे में बताया गया है। पूरे जिले में 15 एफएसटी टीम पूरे जगह दौरा करके आदर्श आचार संहिता का पालन हो रहा है या नहीं इस पर निगरानी रख रही है। इसी के साथ स्टेटिक सर्विलांस टीम भी नियुक्त की गई है।जितनी भी सभाएं या इवेंट हो रहे हैं सभी की वीडियो ग्राफी भी की जाती है। वीडियोग्राफी के बाद सीडी बनती है। वह वीडियो वीविंग टीम को जमा करते हैं। वीविंग टीम सीडी देखती है और फिर जो खर्च होता है उसे प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाता है।

मतदान केंद्रों में सभी सुविधाएं

सभी मतदान केंद्रों मे सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है।जैसे शौचालय, रैंप, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, शेड जरुर होना चाहिए। जिले में जो दिव्यांगजन हैं और जो सीनियर सिटीजन और 80 प्लस हैं। उनको घर पर वोटिंग की सुविधा का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। उनकी सहमति के अनुसार जितने आवेदन आए हैं उन पर घर पर वोटिंग के लिए उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए अलग टीमें बनाईं गई हैं।कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 टीम बनीं हैं। केशकाल विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 टीम बनी हैं। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार उनके जितने मार्गदर्शन हैं निर्देश है उनके अनुसार जिला प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है।चुनावी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 6 नवंबर को मतदान सामग्री बांटी जाएगी।

बेमेतरा में 236 दृष्बिाधित मतदाता करेंगे मतदान

बेमेतरा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 में दृष्टिबाधित मतदाता अपने परिजन के साथ जाकर मतदान कर सकेंगे। वहीं जो दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल लिपि के जानकार हैं वो स्वयं वोट डाल सकेंगे। ईवीएम के बगल में इस लिपि के माध्यम से प्रत्याशियों के नाम उन्हें मिल जाएंगे। वहीं दिव्यांगों को बूथों तक ले जाने के लिए मतदाता मित्र तैयार रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 69 बेमेतरा में 236 दृष्टिबाधित मतदाता मतदान वाले दिन 17 नवम्बर को अन्य मतदाताओं के साथ अपने मत का प्रयोग करेंगे।

प्रशासन के अनुसार 80 साल या उससे अधिक आयु के और 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले 19 मतदाताओं ने घर पर ही वोटिंग करने के लिए आवेदन दिया है। जिले की तीनों विधानसभा में 4113 दिव्यांग मतदाताओं में से सिर्फ दो ने घर से मतदान की सहमति दी। वही 80 से अधिक उम्र के बुर्जुग मतदाताओं में 17 मतदाताओं ने घर से मतदान करेंगे। 80 उम्र से अधिक मतदाताओं की संख्या 4715 है। कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से ना छूटे इसके लिए घर-घर जाकर मतदान (होम वोटिंग) का विकल्प दिया गया है। इसके अंतर्गत 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को मतदान करने के लिए डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। अब इन वर्गों के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते हैं वे फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन किया कर सकते है। यह प्रक्रिया 14 नवम्बर तक पूरी कर ली जाएगी।

मर्दापाल चौक में जांच के दौरान बड़ी मात्रा में सोना-चांदी के साथ नगद रकम जब्त

कोंडागांव। जिले के एसडीओपी निमितेश सिंह एवं कोंडागांव थाना प्रभारी प्रहलाद यादव के द्वारा मर्दापाल चौक में वाहनों की जांच के दौरान वाहन क्रमांक सीजी 27 एन 5787 के वाहन स्वामी सूरज सोनी कोंडागांव के कार से सोना 300 ग्राम एवं चांदी 25 किलोग्राम के साथ ही नगद 2500 रुपए बरामद किया है। एक अन्य वाहन क्रमांक सीजी 04 एडब्लू 0308 के वाहन स्वामी नेमीचंद सोनी कोंडागांव के कार से नगद रकम 29600 रुपए, सोना 400 ग्राम चांदी 150 ग्राम बरामद किया गया है। एक अन्य वाहन इनोवा क्रिस्टा क्रमांक सीजी 04 एमयू 0566 के वाहन स्वामी निशान्त के कार से 2 लाख 24 हजार 500 रुपए नगद बरामद किया गया है। एक अन्य वाहन मारूती कार क्रमांक सीजी 27 एक 4194 के वाहन स्वामी कैलाश सोनी के कार से सोना 200 ग्राम कीमत, चांदी 30 किलोग्राम बरामद कर वाहन मालिकों से पूछताछ एवं सामग्रियों के संबंध में जांच के लिए एफएसटी की टीम को तलब कर सुपुर्द किया गया। एफएसटी टीम के द्वारा जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

सामान्य प्रेक्षकों व व्यय प्रेक्षकों ने राजनीतिक दलों की ली बैठक

■ **निर्वाचन व्यय के संबंध में दी जानकारी**

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक आईएएस श्रीमती रूपांजलि कार्तिक, आईएएस श्री सी.एन.लोंगफई, आईएएस श्री ससीम कुमार बरई व व्यय प्रेक्षक द्वय श्री ओमप्रकाश व श्री पी.सुगेन्द्रन ने आज संयुक्त रूप से निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक ली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल भी बैठक में सम्मिलित हुए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्दर यादव एवं अपर कलेक्टर श्री राजीव कुमार पाण्डेय भी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोयल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा के प्रत्याशियों के व्यय हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय सीमा निर्धारण किया गया हैं। उन्होंने व्यय लेखा मैंटेन करने के साथ लेखांकन टीम के पास संधारित

करवाना आवश्यक है। इसके साथ उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के व्यय निगरानी के लिए वीएसटी द्वारा वीडियोग्राफी करायी जाएगी। जिसका अवलोकन कर व्यय का संधारण किया जाएगा। इसके साथ ही पेयजल, दरी, फैन, पंडाल जैसे विभिन्न सामग्रियों के साथ वाहन, नाचा दल, आदि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दर का निर्धारित किया गया हैं।

प्रचार सामग्री वाहन के संबंध में बताया कि अनुमति लेकर कार्य करें, इसके साथ ही बैनर में मुद्रक एवं प्रति अनिवार्य रूप से अंकित किया आवश्यक हैं। इसके साथ ही खर्च में अंतर पाए जाने पर आप अपील कर सकते हैं। कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि प्रत्याशियों के विज्ञापन व्यय के लिए एमसीएमसी गठित की गई हैं। जिसमें मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही हैं, मीडिया में विज्ञापन की दर निर्धारित होने के साथ ही इस बार सोशल मीडिया का दर भी निर्धारित किया गया हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सभी आचार संहिता का पालन करेंगे एवं प्राप्त नोटिस का निर्धारित समय अवधि में जवाब देना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

चुनाव आयोग की नई पहल, 82 वर्ष के बुजुर्ग व दिव्यांग फुलकुंवर ने घर में किया मतदान

कोंड़ागांव। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर व्यस्क को अपने मत से सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के उपयोग के लिए युवा उत्साहित रहते हैं, ऐसे ही अपने मतों के अधिकार के उपयोग के लिए लालायित सिदावंड की फुलकुंवर नेताम को 35 वर्ष की उम्र में पहली बार वोट देने का अवसर मिला। दरअसल फुलकुंवर नेताम बचपन से ही अज्ञात बीमारी के कारण चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गई थी। चुनावों के दौरान लगने वाली लंबी लाईनों से बचाने के लिए परिजन भी फुलकुंवर भी मतदान केंद्र ले जाने में परहेज करते थे। फुलकुंवर के वोट देने की इच्छा इस विधानसभा चुनाव 2023 में जाकर पूरी हुई, जब भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए घर में ही मतदान करवाने की व्यवस्था की, इसके लिए घर में ही मत देने के इच्छुक मतदाताओं से आवेदन लिए गए थे।

कोंडागांव जिले के सिदावंड गांव में मतदान दल के पहुंचने की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। मतदान दल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दल पहुंचा और घर में ही मतदान की सुविधा प्रदान की। मतदान कर फुलकुंवर बहुत खुश थी। बड़ेकनेरा की रहने वाली पीते पोयाम वर्षों से अपने बिस्तर से उठ पाने और बोलने में

असमर्थ रहीं हैं। घर पर अकेली रहने वाली 82 वर्षीया पीते की सेवा उनकी व्याहता बेटी और दामाद किया करते है। मतदान केंद्र तक जाने की असक्षमता के कारण वह मतदान नहीं कर पाती थी, इस बार मतदान अधिकारी जब घर पहुंचे तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि मतदान केंद्र खुद उनके पास चलकर आया है। पीते बहुत खुश थीं उन्होंने दामाद की सहायता से मतदान की प्रक्रिया पूरी की।

गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में मतदान केंद्रों तक पहुंच पाने में असमर्थ दिव्यांगों और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए डाकमत पत्र की व्यवस्था की गई है। जिसके लिए दोनों विधानसभाओं मोबाइल मतदान दलों का गठन कर घर-घर जाकर मतदान कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत कोंडागांव विधानसभा में 5, नारायणपुर विधानसभा (आंशिक) में 1 एवं केशकाल विधानसभा में 6 दलों को नियुक्त किया गया है। जिसमें घर घर किये गए विशेष संक्षिप्त सर्वेक्षण में बीएलओ द्वारा चिन्हित कुल 178 मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसमें कोंडागांव विधानसभा-83 में 82, नारायणपुर विधानसभा-84 (आंशिक) में 02 और केशकाल विधानसभा-82 के 94 मतदाता शामिल हैं जिसमें 36 दिव्यांग और 140 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

माओवादियों ने किया चुनाव का बहिष्कार

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की

उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है विधानसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 7 नवंबर को वोटिंग है। बस्तर छत्तीसगढ़ का सबसे संवेदनशील मतदान क्षेत्र में माना जाता है जो कि यहां नक्सलवाद चरम पर है, जिसके कारण पहले चरण के चुनाव को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़िया भी भेजी गई है। इस दौरान आज नक्सलियों ने फिर चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया है नक्सलियों ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि चुनाव अधिकारियों को एवं चुनाव कर्मियों को हमारी अपील है कि 7 नवंबर को होने वाला चुनाव मैं हमारे संघर्ष वाले एरिया में आएंगे जहां आपकी जान को खतरा है,आप यहां ना आकर अपने आप को सुरक्षित रखें।

लक्ष्मी देवांगन के खिलाफ लामबन्द हुआ देवांगन समाज

कोरबा। विधानसभा चुनाव 2023 के जोर पकड़ते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कुछ दिन पूर्व देवांगन समाज के लक्ष्मी देवांगन ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि जब लखन लाल देवांगन महापौर थे तब समाज के लिए जमीन की मांग की गई थी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब वह संसदीय सचिव बने तब भी उनसे समाज के लिए जमीन मांगी गई तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वही जयसिंह अग्रवाल से जमीन मांगी गई तो तत्काल उन्होंने जमीन देते हुए भूमिपूजन किया। जब खुद लखनलाल विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तब उन्हें समाज की याद आ रही है। लक्ष्मी देवांगन का वीडियो जारी होते ही पलटवार करते हुए भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन के समर्थन में समाज के लोग सामने आए हैं। बुधवारी बाजार स्थित परशुराम भवन में एक बैठक कर लक्ष्मी देवांगन के आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया की लक्ष्मी देवांगन समाज के कोई अध्यक्ष नहीं है। गिरधारी लाल देवांगन छुरी निवासी ने कहा कि लक्ष्मी देवांगन कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं।

खरसिया से 2 एवं रायगढ़ से 1 नामांकन अवैध पाये गये

रायगढ। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए जिले की चार विधानसभाओं हेतु 30 अक्टूबर तक नामांकन के पश्चात आज 31 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (स्कुटनी)की गई। जिसके पश्चात खरसिया विधानसभा से 2 नामांकन तथा रायगढ़ से एक नामांकन को रिटर्निंग आफ्सिर्स ने अवैध घोषित किया तथा लैलूंगा से 9, रायगढ़ से 23, खरसिया से 8 एवं धरमजयगढ़ विधानसभा से 7 अभ्यर्थियों के नामांकन को वैध पाया गया। इस संबंध में जिला निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरसिया विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमती पूर्णिमा विजय जायसवाल (आम आदमी पार्टी) तथा श्री कीर्ति कुमार राठिया (गोंडवाना गणतंत्र पार्टी)के नामांकन को अवैध घोषित किया गया। वहीं रायगढ़ विधानसभा के श्री अरूण अग्रवाल (आम आदमी पार्टी) के नामांकन को संवीक्षा उपरांत अवैध घोषित किया गया। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 2 नवम्बर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे।

मानव श्रृंखला से शत-प्रतिशत मतदान करने किया प्रेरित

राजनांदगांव। विधानसभा निर्वाचन 2023 में शत प्रतिशत मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत डोंगरगांव विकासखंड के डॉ. बीआर अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह ने उपस्थित सभी को मतदान करने और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वसहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में मानव श्रृंखला द्वारा 7 नवम्बर वोट लिख कर मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया गया। सभी ने मैं भारत हूं... गीत का गायन किया और मतदाता जागरूकता के लिए सारे काम छोड़ दो... 7 नवम्बर को वोट दो... के नारे भी लगाए। कार्यक्रम में 7 नवम्बर को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया और मतदान के महत्व के संबंध में जानकारी दी गई।

भाजपा के झंडों की चोरी पुलिस में शिकायत

कोरबा। चुनावी हलचल के बीच अब पार्टी

के झंडे चोरी होने लगे हैं। भाजपा के एक पदाधिकारी ने पार्टी का झंडा चोरी होने और निकाल कर फेंके जाने की शिकायत सर्वमङ्गला पुलिस सहायता केंद्र में की है। भाजपा किसान मोर्चा के कार्यालय प्रभारी माखन यादव ने लिखित शिकायत करते हुए बताया है कि वार्ड 50 सर्वमंगला नगर के बरमपुर चौक पर भाजपा पार्टी का झण्डा समस्त दुकानदारों के समर्थन से लगाया गया था जिसे आज अर्ध रात्रि किसी व्यक्ति द्वारा सभी झण्डा को चोरी कर ले गया एवं निकालकर फेंक दिया गया है जिससे सौहार्द बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। इस प्रकार का कृत्य करने वालो पर कार्यवाही करने की आवश्यकता शिकायतकर्ता ने बताई है। भाजपा के झण्डा की चोरी कर निकाल कर फेंकने की शिकायत पर उचित कार्यवाही की मांग की गई है।

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन से धान खरीदी की शुरुआत

■ **चुनावी शोर में धान तिहार की तैयारी अधूरी, टारगेट भी बढ़ाया**

कोरबा। छत्तीसगढ़ में धान तिहार शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। हालांकि चुनावी साल की वजह से फिलहाल धान खरीदी को लेकर उतना उत्साह नहीं दिख रहा। वहीं धान खरीदी के लिए टोकन भी गिने चुने ही कटे हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कोरबा जैसे आदिवासी जिलों में धान बेचने के लिए एक भी टोकन नहीं कट सका है।

केंद्र सरकार ने धान खरीदी केंद्रों में इस बार बायोमेट्रिक मशीन की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी भी केंद्र में बायोमेट्रिक मशीन की व्यवस्था फिलहाल नहीं हो सकी है। राज्य सरकार के सचिव ने सभी कलेक्टर और

संभाग आयुक्तों को पत्र लिखकर बिना बायोमेट्रिक के ही धान खरीदी की शुरुआत करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बायोमेट्रिक मशीन लगाने के लिए टेंडर हो चुका है। बायोमेट्रिक मशीन के लिए जिस कंपनी को टेंडर मिला है, उसने धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक की व्यवस्था के लिए थोड़ा समय मांगा है। यही वजह है कि फिलहाल बिना बायोमेट्रिक के ही धान खरीदी होगी।

पिछले साल छत्तीसगढ़ में 23 लाख 42 हजार किसानों से धान खरीदी हुई थी। धान के बदले करीब 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किसानों को हुआ। सहकारी समितियों में इस बार 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट रखा गया है।

साल 2022-23 में छत्तीसगढ़ में 107 लाख 51 हजार 858 मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना। साल 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड था। अब इस साल पुराने रिकॉर्ड टूटने का भी अनुमान है। दरअसल सरकार ने प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा को 15 से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिया है, लिहाजा ज्यादा धान खरीदी होना तय है।

छत्तीसगढ़ में 26 लाख 48 हजार किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। किसानों की कर्जमाफी के बाद मौजूदा वर्ष में 2 लाख 42 हजार नए किसानों ने पंजीयन कराया है। धान बेचने के लिए किसानों की संख्या बढ़ी है। छोटे किसानों ने भी अपना पंजीयन करा लिया है। अब यह किसान खुले बाजार के बजाय सरकार को धान बेचेंगे ताकि उन्हें समर्थन मूल्य पर ज्यादा लाभ मिल सके।

छत्तीसगढ़ में 2 हजार 497 धान खरीदी केंद्र हैं। पिछले साल नए धान खरीदी केंद्र भी खुले हैं। कुछ जगहों पर और भी नए धान खरीदी केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। नए धान खरीदी केंद्र से किसानों को फायदा होगा। किसानों को धान लेकर ज्यादा दूर तक सफर नहीं करना पड़ेगा।

बेलबेहरा के जंगलों में हाथियों की दहशत ग्रामीणों की फसल की बर्बाद

कोरिया। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हाथियों का आतंक देखने को अक्सर मिलता है।सरगुजा,रायगढ़ और कोरबा वनपरिक्षेत्र में हाथियों का अक्सर आना जाना लगा रहता है।लेकिन इस बार कोरिया वनपरिक्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचाया है। दो हाथियों के दल ने कोरिया वन मंडल के गांवों में आतंक मचा रखा है।

शुक्रवार की देर रात दो हाथियों का समूह मरवाही के इलाके से होता हुआ एमपी के जैतहरी वनपरिक्षेत्र को पार करके सुबह 6 बजे धनगवां बीट के जंगल में पहुंचा ।इसके बाद भलुहानटोला जंगल से निकल कर चोई गांव पहुंचा।जहां अनुरुप सिंह और उनके परिजनों के खेतों में लगी धान की फसल को बर्बाद कर दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया वन परिक्षेत्र अंतर्गत भौता में रुकने बाद टांकी बीट के पडरी झोरखी नामक जगह में ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाया।

खड़गवां वन परिक्षेत्र के बेलबहरा जंगल में दोनों विचरण कर रहे हैं। इन दोनों हाथी कोरिया वन मंडल की सीमा के पास जंगल में मौजूद हैं। खड़गवां के पास मौजूद हाथियों ने ग्रामीणों की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। जिससे ग्रामीण परेशान हैं।ग्रामीण अब फसलों की रक्षा के लिए रातजगा करने को मजबूर हैं। हाथियों के गांव के आस-पास घूमने से वन विभाग भी चौकन्ना है। विभाग की टीम हाथियों के मूवमेंट की निगरानी रख रही है। साथ ही ग्रामीणों को हाथियों के पास नहीं जाने की सलाह भी दी जा रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने धान की फसल नुकसान का आंकलन करने के बाद मुआवजा देने की बात कही है।

हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी, भाजपा वाले बताएं उन्होंने क्या किया: खड़गे

सुकमा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। सभी दलों के नेता वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और उन्होंने सुकमा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। खरगे से पहले सीएम बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि पहली बार खरगे आये हैं उनका ताली बजा कर स्वागत करें। सीएम ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान में कुछ समय रह गया है आज का दिन विशेष है। आज के ही दिन हमारा राज्य बना क्योंकि चुनाव चल रहा है अचार सहिता लगा है इसलिए भव्य कार्यक्रम नही हो रहा है। हम केवल तीन साल सत्ता में रहे दो साल कोरोना में बीत गया हमने फिर भी विकास किया।

सीएम बघेल ने पूर्व की रमन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रमन सिंह के राज में आदिवासियों पर अत्याचार , फर्जी एनकाउंटर होता था वनोपज का हमने सही मूल्य दिया मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपको कभी सही रेट मिल, हर चीज में कमीशन चलता था। मोबाइल से लेकर चप्पल तक मे कमीशन चलता था, हम जब भी सुकमा आते थे कभी भी जिस रास्तेसे जाते थे दोबारा उस रास्ते से नही आते थे नक्सलियों की वजह से हमने यहां पर शिक्षा का स्तर बदल दिया।

कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया

सीएम ने कहा कि प्रदेश में यहां के बच्चों ने टॉप

किया फिर से किसानों का कर्ज माफ होगा धन्यवाद देने की लिये फिर से कांग्रेस की सरकार बनाइये, पढ़ाई के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं आपके पढ़ाई का खर्चा हमारी कांग्रेस पार्टी उठाएगी, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपका इलाज आपके घर के पास होगा , सिलेंडर रिफिल करवाने पर 500 आपके खाते में आयेंगे, राशन फ्री में देंगे जिससे घर चलाना आसान हो जायेगा। सीएम ने कहा कि चुनाव सर पर हैं पर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वादा नहीं किया कि छत्तीसगढ़ के लिए वे क्या करेंगे वे झूठ बोलने में माहिर है, उनकी बातों की कोई गारन्टी नहीं है , हमने 16 गारन्टी दी।

सीएम के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि सभी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बधाई, मैं इस चुनावी दौरे में आपसे वोट मांगने नही आया, मै आपसे विनती करता हूँ आप लोगों को संविधान को ओर देश को बचाना है। इस इलाके में कोई स्कूल नही था, कोई बाजार नही था, जो किया कांग्रेस ने किया। खरगे ने कहा कि जो पूछते हैं हमने क्या किया उन्हें एक बार इस इलाके में आ कर देखना चाहिए। खरगे ने कहा कि कांगेस ने जो विकास किया इसे सभी को देखना चाहिए छत्तीसगढ़ आना चाहिए, हमने इस देश और इस इलाके के लिए कुछ किया है तभी हम वोट मांग रहे हैं, आपने क्या किया है जो आप वोट मांग रहे हैं, आपने कांगेस को ताना देने की सिवाय कुछ नही किया, कांगेस पार्टी के प्रधान मंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने देश के लिए जान दे दी और भाजपा के लोग पूछते हैं आपने क्या किया। खड़गे ने आगे कहा कि जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों को उनका हक बघेल सरकार ने दिया, बीजेपी वाले बेचना चाहते हैं, बड़े व्यापारियों को जल, जंगल, जमीन भाजपा वाले बेचना चाहते हैं। हम जो वादा करते है उसे हम पूरा भी करते है , एक ओर हमारी खनिज सम्पत्ति लूटी जा रही है, देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसे आपको देखना चाहिए, मोदी हमेशा बोलते हैं मैं गरीब हूं, मुझे काम करने नही दिया जा रहा, हम जो काम करेंगे देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए करेंगे। खरगे ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की है। हम हमेशा गरीबों के साथ हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमने आजादी के वक्त सीने पर गोलिया खाई, जिन्होंने देश के लिए कुछ नही किया उन्हें ये सब देखना चाहिये, तेंदु पत्ता का दाम हमने बढ़ाया, वन अधिकार पट्टा पूरे देश मे सबसे अधिक हमने दिया, धान का सबसे ज्यादा बोनस हमने दिया , बिजली की व्यवस्था की, मोदी जी छत्तीसगढ़ का विकास देखें, खरगे ने कहा कि योजनाएं आदिवासी भाइयो- बहनों को मिल रही हैं, आदिवासी राष्ट्रपति को भी उन्होंने संसद भवन के उद्घाटन में नही बुलाया,, उद्घाटन भी मोदी ओर शाह ने कर लिया।

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर पीएम राज्यपाल और सीएम ने दी बधाई

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाइयों और बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यहां के लोगों की जीवंतता इसे एक विशेष राज्य बनाती है। इस राज्य की संस्कृति को समृद्ध बनाने में हमारे आदिवासी समुदायों का बहुत ही अहम योगदान है। प्रदेश की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

इस दौरान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ हर वर्ष विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से आव्हान किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सभी ने जो मिलकर सपने देखे हैं, उसे पूर्ण करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें और प्रदेश और देश की प्रगति में सहभागी बनें।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ महतारी के जम्मो लइका, सियान, दाई-दीदी, बहिनी अऊ युवा मन ल 23वां राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा-गाड़ा बधई अऊ शुभकामना। हमर पुरखा मन जेन सपना देखे रिहिस, जेन संघर्ष करे रिहिस, सुग्घर छत्तीसगढ़ के संकल्प लेके ओमन के देखाए रद्दा म चलत हमन पांच बछर म हर छत्तीसगढ़िया के जीवन म बदलाव लाए के काम करे हन। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के संग-संग पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्रप्रदेश अऊ लक्षद्वीप संघ घलो अपन स्थापना दिवस मनावत हे। ए अवसर म मैं ये राज्य मन के जम्मो जनता मन ल घलो बधई देवत हंव।

वहीं स्थापना दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि जम्मो प्रदेशवासी भाई-बहिनी मन ल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधई। आज हमर छत्तीसगढ़ 23 बछर के युवा छत्तीसगढ़ नव उमंग अऊ जोश के साथ विकास के रद्दा म आगु बढ़े बर तैयार हरे, आप सब्बो के सहयोग से हमर परदेश खूब तरक्की करए अईसने कामना हे।

इसी क्रम में अरुण साव ट्वीट कर लिखा कि उत्तर मा हे जशपुर सोहे, मुकुट कस सोहाय, अरपा पैरी अउ महानदी हा बोहाय, 18 गढ़ रतनपुर त 18 रइपुर के आए, उहे ले तोर छत्तीसगढ़ नाम कहाय। आप जम्मो छत्तीसगढ़वासी मन ला छत्तीसगढ़ सृजन दिवस के गाड़ा-गाड़ा बधाई।

संक्षिप्त समाचार

रंजीत रंजन 3 व 4 को करेंगे राजनांदगांव व कोण्डागांव में जनसंपर्क

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं स्टार प्रचारक व राज्यसभा सांसद श्रीमती रंजीत रंजन 3 नवंबर को राजनांदगांव व 4 नवम्बर कोण्डागांव में चुनाव प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार रंजन तीन नवंबर को सुबह 11 बजे राजधानी रायपुर से राजनांदगांव के लिये रवाना होंगे। 1 राजनांदगांव आगमन एवं दरगाह में मुस्लिम समाज के साथ बैठक में भाग लेंगे, 3 राजनांदगांव गुरुद्वारा में सिख समाज के साथ बैठक/ भेंट चर्चा, 5 टेडेसरा (राजनांदगांव ग्रामीण) जनसपंर्क कार्यक्रम में भाग लेंगी, 7 राजनांदगांव से रायपुर के लिये रवाना होंगे। 4 नवम्बर को सुबह 8 रायपुर से कोण्डागांव के लिये प्रस्थान करेंगे जहां 1 तहसील पारा में आयोजित नुक्कड़ सभा एवं जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लेंगी, 3 केशकाल में रोड शो एवं सभा को संबोधित करेंगे, 6 केशकाल से रायपुर के लिये प्रस्थान एवं 9 रायपुर आगमन एवं रात्रि विश्राम करेंगे।

राहुल 4 को आएंगे जगदलपुर, गैदू बनाए गए कार्यक्रम समन्वयक

रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी प्रचार-प्रसार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी 4 नवंबर को जगदलपुर में आयोजित आमसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त किया है।

भाजपा ने लॉन्च किया अपना चुनावी एंथम और रैप सांग

रायपुर। छत्तीगसढ़ में अगले महीने प्रस्तावित चुनाव के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई हैं, पक्ष और विपक्ष में सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी ने अपना चुनावी एंथम लॉन्च किया है। बीजेपी ने इसे छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी 3 भाषाओं में बनाया है। आज बीजेपी के एंथम की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, सह प्रभारी नितिन नबीन, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के अलावा कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।

कलेक्टर डॉ. भुरे ने मंदिर हसौद उपार्जन केंद्र में धान खरीदी का किया शुभारंभ

रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज जिले के मंदिर हसौद स्थित उपार्जन केंद्र में धान खरीदी का पुजा अर्चना कर शुभारंभ किया। आज 01 नवम्बर से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। डॉ. भुरे ने केंद्र में आए किसान श्री गणेश राम बंजारे का स्वागत किया। श्री बंजारे ने केंद्र में 30 क्विंटल बेचा। डॉ. भुरे ने संबंधित विभागिय अधिकारियों को केंद्र में बारदाना, धान को बारिश से बचाने के लिए कैप कवर, नमी मापने आद्रतामापी यंत्र क्रय कर केलिब्रेशन, उपार्जन केंद्र में कर्मचारी एवं डाटा एंट्री आपरेटर की नियुक्ति, पर्याप्त संख्या में हमालों की संख्या, प्राथमिक उपचार एवं पंजीयन के लिए आने वाले किसानों हेतु पीने के पानी की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि है जिले के अन्य केंद्रों में भी धान खरीदी के लिए पुख्ता इतजाम किया जाए ताकि किसानों को तकलीफ न हो। जिले में 139 धान उपार्जन केंद्र है। गौरतलब है कि गतवर्ष जिले में 52 लाख क्विंटल

धान खरीदा गया था। इस वर्ष 68 लाख क्विंटल खरीदने का लक्ष्य है। इस अवसर पर आरंग एसडीएम श्री अतुल विश्वकर्मा, उप पंजीयक श्री आर के चन्द्रवंशी और कॉपरेटिव बैंक अधिकारी श्री प्रभात मिश्र , सहायक खाद्य अधिकारी श्री अरविंद दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, शाह और योगी भी करेंगे प्रचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा जारी है। सभी केंद्रीय नेताओं का आने-जाने का सिलसिला जारी है। सभी प्रचार-प्रसार के साथ ही अपने प्रत्याशियों का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे सभी 4 नवंबर को प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करेंगे।

पीएम मोदी नवंबर महीने में 15 दिनों के भीतर तीन बार छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। वे दो नवंबर को कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सात नवंबर को सरगुजा के दौरे पर रह सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी विश्रामपुर और सूरजपुर में सभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ

ही वो 14 नवंबर को रायपुर में रोड शो भी कर सकते हैं। दो नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुनावी सभा कांकेर में होने वाली है, जिसकी तैयारी के लिए भाजपा कार्यालय कमल सदन कांकेर में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितीन नवीन ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

इस दौरान नवीन ने बताया कि दो नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा होनी है, जिसकी तैयारी अच्छे से करनी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं मे जोश भरेंगे और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए जनता से अपील भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सभा में कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, केशकाल, सिहावा, डोंडीलोहारा, धमतरी, बालोद और गुंदरदेही विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे।

पीएम मोदी दो नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वे चार नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दुर्ग में आमसभा को संबोधित कर सकते हैं। अमित शाह तीन और चार जगहों पर रोड शो के साथ ही सारंगढ़, पलारी और आरंग में आमसभा को संबोधित करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ भी दो दिनों में अलग-अलग विधानसभाओं को संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी जारी कर सकते हैं छग भाजपा का घोषणा पत्र, बस्तर पर हो सकता है फोकस

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भले ही घोषणापत्र जारी ना किया हो।लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपनी सभाओं में बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इन घोषणाओं को ही कांग्रेस अपने घोषणापत्र में शामिल कर सकती है।वहीं बात बीजेपी की करें तो अब तक पार्टी ने एक भी घोषणा नहीं की है।ना ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने मंच से कोई ऐसी बात की है जिसका असर जनता पर हो।अब तक प्रदेश में हुई सभाओं में जितने भी बीजेपी के स्टार प्रचारक आए उन्होंने सिर्फ मोदी के कार्यकाल को ही सामने रखा।ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 नवंबर को पीएम मोदी की कांकेर की सभा में बीजेपी का घोषणापत्र जारी कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में बस्तर के वोटों की अहमियत हर कोई जानता है। हर राजनीतिक दल के पास बस्तर को जीतने की चुनौती रहती है।बीजेपी की बात करें

तो मौजूदा समय में बस्तर से पार्टी का सूपड़ा साफ है।कभी बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला बस्तर अब कांग्रेस का किला बन चुका है।इस किले में सेंधमारी करने के लिए पार्टी ने पीएम मोदी की ज्यादातर सभाएं बस्तर संभाग में ही रखी है।ताकि मोदी का फैक्टर काम कर जाए।पीएम मोदी ने पिछले महीने बस्तर को नगरनार स्टील प्लांट की सौगात देकर एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया।लेकिन कांग्रेस ने इस हवा को ये कहकर फैलने से रोका कि केंद्र सरकार नगरनार प्लांट को निजी हाथों में सौंप सकती है। लिहाजा अब एक बार फिर पीएम मोदी बस्तर के कांकेर में सभा के जरिए एक बड़ा माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे।

चुनाव में घोषणापत्र के क्या मायने होते हैं।ये जानना हो तो छत्तीसगढ़ का पिछला चुनाव उठाकर देख लिए लिजिए।कांग्रेस ने जिस तरह की तैयारी के बाद घोषणापत्र जनता के सामने लाया और बाद में उसे पूरा किया उसका असर कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस के कैंपेन में दिख रहा है।लिहाजा इस बार भी कांग्रेस अपने पुराने घोषणापत्र से एक कदम आगे चलते हुए दिग्गज नेताओं की रैली में कई घोषणाएं कर डाली।वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की घोषणाओं का काट जरूर तैयार किया होगा।और पार्टी अपने सबसे बड़े ग्लोबल फेस यानी पीएम मोदी के हाथों छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए घोषणाओं को जारी करवा सकती है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल और बीजेपी थिंक टैंक ने घोषणापत्र बना लिया है।लेकिन कोई भी नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहा।

लोककल्याण हैं जरुरी, लेकिन नक्सलवाद को नहीं किया जा सकता खत्म : टंडन

रायपुर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में द्वितीय कमान अधिकारी डा. विनोद कुमार टंडन ने अपने द्वारा लिखे नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयास और इस पर पुलिस प्रशासन की भूमिका और वर्तमान परिदृश्य पुस्तक का आज प्रेस क्लब में विमोचन किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में 1967 की विजयी गाथा से लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ में 7 मई 2023 को अरणपुर में हुई घटना का जिक्र किया गया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी वहां कब्जा कर अलग देश की मांग करते हुए आए दिन कश्मीर के रहने वाले भाई-बहनों पर हमला कर रहे हैं और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में नक्सली व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर ग्रामीणों व जवानों पर हमला कर रहे है। नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से कभी खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन कुछ हद तक रोका जरुर जा सकता है, इसके लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन के साथ ही आम जनता को भी कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं को वहां रहने वाले निवासियों तक अगर पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो नक्सली घटनाएं कुछ हद तक जरुर कम हो जाएगा। नक्सली वे लोग बनते हैं जिनके पास राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं और वे निराश और हताश होकर माओवादियों के शरण में चले जाते है और वहीं से वे ट्रेनिंग लेकर नक्सली बनते हैं।

कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय चाहते थे अमित जोगी, शर्त जिसने उन्हें भूपेश का दुश्मन बना दिया

रोहित मिश्र

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके नामांकन दाखिल करते ही यह सीट बेहद दिलचस्प हो गई है। ऊपर से भले ही यह दो राजनीतिक दलों की चुनावी लड़ाई लगती हो लेकिन तहों में जाने पर यह बेहद निजी लड़ाई मालूम पड़ती है।

अमित जोगी कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। पिता अजीत जोगी के साथ कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने 2016 में नई पार्टी बनाई। 2018 के विधानसभा चुनावों में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बसपा के साथ एलांयस किया। अजीत जोगी की पार्टी को पांच और बसपा को दो सीटें मिलीं। राज्य में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार आ गई। 2020 में अजीत जोगी नहीं रहे। अजीत जोगी के निधन के बाद उनकी पत्नी रेणु जोगी ने इस पार्टी का विलय कांग्रेस में करने की कोशिशें शुरू कीं। यह कोशिशें करीब-करीब परवान भी चढ़ गईं थीं लेकिन एक शर्त की वजह से सब कुछ रुक गया।

अजीत जोगी के ना रहने के बाद उनकी पत्नी और पूर्व कांग्रेस नेता रेणु जोगी इस पार्टी का विलय कांग्रेस में चाहती थीं। वह लंबे समय से कांग्रेस में विधायक रह चुकी थीं। उन्होंने स्टेट लीडरशिप के साथ-साथ कांग्रेस हाईकमान से भी बात शुरू की। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि उनकी सोनिया गांधी से इस विषय में बात हो रही थी। सोनिया और रेणु की दशकों पुरानी जान-पहचान थी। सोनिया इस विलय के खिलाफ नहीं थीं लेकिन उन्होंने अंतिम फैसला लेने के लिए राज्य की ईकाई को ही अधिकृत किया। रेणु के संबंध राज्य की ईकाई के नेताओं के साथ बहुत मधुर तो नहीं थे लेकिन खटासपूर्ण भी नहीं थे। पार्टी के नेताओं के साथ बात शुरू हुई। लेकिन कांग्रेस की राज्य ईकाई ने उनके सामने एक शर्त रख दी। यह विलय की ऐसी शर्त थी जिसे पूरा कर पाना संभव नहीं था।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस विलय के खिलाफ थे। वह किसी भी हालत में जोगी परिवार की कांग्रेस में फिर से एंट्री नहीं चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई बताते हैं कि राज्य का कोई भी नेता इस पार्टी के विलय को लेकर सहज नहीं था। उसकी एकमात्र वजह अमित जोगी थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंह देव सहित पूरी टॉप लीडरशिप इस विलय के खिलाफ थी। चूंकि सोनिया गांधी इस विलय के खिलाफ नहीं थीं इसलिए पार्टी के नेताओं ने रेणु को दो टूक तो मना नहीं किया लेकिन

उनके सामने एक शर्त रख दी गई। रेणु जोगी से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को कांग्रेस में ले लेगी लेकिन वह अमित जोगी को नहीं लेगी। अमित के बिना यदि पार्टी विलय करना चाहती है तो विचार किया जा सकता है। जैसा कि स्वाभाविक ही थी इस शर्त के बाद विलय की बात टूट गई। इसी के साथ भूपेश बघेल और जोगी परिवार के बीच की राजनीतिक तल्खी एक निजी तल्खी में बदल गई। पाटन की सीट से उनका नामांकन दाखिल करना राजनीतिक पंडितों को राजनीति से ज्यादा निजी लग रहा है।

रेणु जोगी शुरुआत से ही नई पार्टी बनाने के खिलाफ थीं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि खुद अजीत जोगी भी नई पार्टी बनाने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं थे। कांग्रेस से करीब-करीब साइड लाइन कर देने के बाद अमित जोगी की जिद पर ही नई पार्टी बनाई गई। राजनीतिक जानकार वो वाकया भी नहीं भूलते जब पार्टी की स्थापना दिवस पर खुद रेणु जोगी मंच पर सबसे देर में आईं और सबसे पहले चली गईं। नई पार्टी के गठन के बाद वह कांग्रेस की मेंबर बनी रहीं। वह पार्टी की मीटिंग अटेंड करतीं। इससे एक किस्म की असहजता पार्टी में बनी रहती। इस बीच ना तो रेणु जोगी ने पार्टी छोड़ी और ना ही पार्टी ने उन्हें निकाला।

2018 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अपने उम्मीदवारों का एलान कर रही थी। उस समय तक भी रेणु जोगी कांग्रेस पार्टी में बनी रहीं। कांग्रेस के लिए असहजता बढ़ती गई। कांग्रेस ने जब रेणु जोगी की पारंपरिक सीट कोटा से किसी और प्रत्याशी की घोषणा कर दी तब उसके बाद रेणु जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सदस्यता ली और उस पार्टी ने नामांकन दाखिल किया। एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने कभी भी रेणु जोगी को पार्टी ने निकाला नहीं। सूत्र बताते हैं कि सीएम भूपेश को छोड़कर रेणु जोगी के संबंध पार्टी के बाकी नेताओं के साथ तल्खी वाले नहीं हैं।

पाटन की सीट अब दिलचस्प हो गई है। पहले यहां पर भूपेश बघेल और बीजेपी के दुर्ग से सांसद विजय बघेल के बीच सीधी लड़ाई थी। विजय बघेल 2008 के चुनाव में भूपेश को हरा भी चुके हैं। अमित जोगी ने बिल्कुल आखिरी में इस लड़ाई में एंट्री मारी है। उनके आने से यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पत्रकार रवि भोई कहते हैं कि पाटन सीट पर सतनामी समाज के वोटरों की संख्या ठीक-ठाक है। सतनामी समाज के लोग जोगी के पारंपरिक वोटर रहे हैं। यदि बड़ी संख्या में वोटर अमित जोगी के पक्ष में आते ही तो निश्चित ही भूपेश के सामने चुनौती खड़ी होगी। हालांकि भोई कहते हैं कि पाटन की सीट पर भूपेश का अच्छा प्रभाव है उनको वहां जीतने में समस्या नहीं आएगी लेकिन अमित जोगी इस लड़ाई को कठिन जरुर बनाएंगे। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि अमित जोगी बीजेपी की शह पर काम कर रहे हैं। टिकट बंटवारे से लेकर उनके पूरे चुनाव प्रबंधन तक को बीजेपी मैनेज कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया तो विरोधियों को यह कहने का मौका मिला कि बीजेपी और अमित जोगी में सांठ-गांठ हैं। कांग्रेस, अमित जोगी को बीजेपी की बी टीम बताती आ रही है। हालांकि जोगी इस आरोप को सिरे से खारिज करते रहे हैं।

सहयोगियों की अनदेखी करती कांग्रेस

उमेश चतुर्वेदी

मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरह विपक्षी गठबंधन के बीच खींचतान उभरी है, उससे विपक्षी राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं। बेशक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन तीनों ही राज्यों के कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां कभी समाजवादी वैचारिकी की तूती बोलती थी। विशेषकर गुजरात सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसी स्थिति रही है। फिर बुंदेलखंड ऐसा इलाका है, जहां समाजवादी पार्टी का अपना असर रहा है। पिछले नगर निकाय चुनावों में जिस तरह उत्तर प्रदेश से सटे सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर चुनवा लिया, उससे साफ लग रहा है कि छोटी दिखने वाली इन पार्टियों की कुछ इलाकों में अपनी खास भूमिका होती है। लेकिन कांग्रेस ने इन चुनावों में अपने इन साथी दलों और उनके नेताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, उससे नहीं लगता कि गठबंधन में सबकुछ ठीक चल रहा है। विपक्षी गठबंधन में निश्चित रूप से कांग्रेस सबसे पुराना और सबसे बड़ा दल है। इस नाते भले ही वह गठबंधन की अगुआई करे, लेकिन उसे नहीं भूलना चाहिए कि अब दुनिया आगे निकल चुकी है। बेशक वह बड़ा दल है, लेकिन जमीन पर उसकी पकड़ कैसी है, यह छिपी बात नहीं रही। फिर वह अतीत के ही आधार पर खुद को आंक रही है। वह स्वीकार नहीं कर पा रही है कि सुनहरे इतिहास के पन्ने अब धुंधले हो गए हैं। सांसदों की संख्या के हिसाब से विपक्ष में तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। लेकिन गठबंधन में ममता बनर्जी की दिलचस्पी कम दिख रही है और लगता है कि वे बांग्ला माटी में उसके इस्तेमाल की गुंजाइश परख रही हैं। ऐसे ही जनता दल यूनाइटेड भी बड़ा दल है, भले ही उसके सांसदों की संख्या की वजह बीजेपी का साथ रही। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी महत्वपूर्ण दल है और वहां वही बीजेपी के सीधे मुकाबले में है। इस लिहाज से सपा की अहमियत की चाहत स्वाभाविक है। इसी वजह से अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में अपने लिए कुछ सीटों की उम्मीद रखी। लेकिन कांग्रेस ने बात सुनना तो दूर, उन्हें अपमानित ही किया। कमलनाथ का कहना कि 'छोड़िए अखिलेश-वखिलेश को' – उनके प्रति कांग्रेस के भाव को जाहिर करता है। रही-सही कसर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की बदजुबानी ने पूरी कर दी। ऐसे में अखिलेश ने आपा खो दिया। इसका असर उत्तर भारत के तीनों राज्यों में दिख रहा है, जहां सपा भी मैदान में है। कुछ मोदी विरोधी समीक्षकों की राय में मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस अध्यक्ष का पद दमदार तरीके से संभाल रहे हैं। यह ये जाहिर करने की कोशिश है कि राहुल गांधी बेहद लोकतांत्रिक हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में कांग्रेस पर नियंत्रण राहुल गांधी का ही है। अगर इन चुनावों में नीतीश को किनारे रखा जा रहा है या फिर अखिलेश पर कांग्रेसी हमला हो, या फिर आम आदमी पार्टी की उपेक्षा हो, इन सबके पीछे राहुल की ही सोच मानी जा रही है। राहुल गांधी जाति जनगणना के बड़े पैरोकार बनकर उभरे हैं। कांग्रेस के नेता राज्यों में वादा कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार बनी, वह जाति जनगणना कराएगी। राजस्थान में तो ऐन चुनावों के बीच अशोक गहलोत ने ऐलान भी कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसपर रोक लगा दी। जाति जनगणना की मांग या इसे लागू करने का असल मकसद पिछड़े वर्गों को फायदा पहुंचाने से ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाना है। राहुल गांधी भी इसी वजह से बार-बार इस मसले को उठा रहे हैं। अगर जाति जनगणना का मुद्दा विकास की दौड़ में पीछे रह गयी जातियों को फायदा

ममता बनर्जी की भूख हड़ताल

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए खुद को उद्योग हितैषी दर्शाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी सरकार का दावा है कि राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल है इसलिए किसी को भी मौका चूकना नहीं चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार इसी नवंबर माह में 21 और 22 तारीख को कोलकाता में ग्लोबल बिजनेस समिट भी आयोजित कर रही है। इस बिजनेस समिट में देश-विदेश के निवेशक आ सकें इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है। हाल ही में ममता बनर्जी स्पेन और दुबई की 10 दिवसीय यात्रा पर भी गयी थीं ताकि निवेशकों को बंगाल में आमंत्रित किया जा सके। लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस का उद्योग विरोधी चेहरा तब फिर सामने आ गया जब एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को निर्देश दिया कि वह घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स को सिंगूर संयंत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे 766 करोड़ रुपये का मुआवजा दे।

देखा जाये तो आज भले ममता बनर्जी कह रही हों कि उनकी सरकार ने राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बनाया है और तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल औद्योगिक विकास के मामले में आगे बढ़ा है लेकिन सच्चाई यह है कि 2006 में ममता बनर्जी ने अपनी छवि औद्योगिक विकास की विरोधी नेता की बना ली थी क्योंकि उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में उद्योगों के लिए किये जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। इसके नतीजतन टाटा नैनो को सिंगूर में अपनी कार परियोजना वापस लेनी पड़ी थी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए टाटा नैनो प्रोजेक्ट को गुजरात के साणंद में लगाने में मदद की और जल्द ही मोदी की छवि उद्योग जगत के बीच विकासशील नेता की बन गयी थी। हालात ऐसे हो गये थे कि बंगाल से निवेशक दूर होते जा रहे थे वहीं गुजरात में देश ही नहीं विदेशी निवेशक भी रुचि दिखा रहे थे।

देखा जाये तो टाटा %नैनो% के निर्माण प्लांट को पश्चिम बंगाल से बाहर भेजने के लिये दबाव डालना %बड़ी भूल% थी और इसने अन्य उद्योगपतियों के लिये बाधाएं पैदा करने का काम किया था। उस समय 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी टाटा मोटर्स के प्रोजेक्ट के उखड़ते दृश्य टीवी पर इतने बार दिखाये गये थे कि हर उद्योगपति ने यह बात अपने पल्ले बांध ली थी कि बंगाल में निवेश से दूर रहना है। इसलिए अब जब राज्य सरकार ग्लोबल बिजनेस समिट आयोजित करने जा रही है तब सिंगूर का भूत एक बार फिर सामने आकर खड़ा हो गया है जिसे देखकर सबके हाथ-पांव फूल रहे हैं।

ममता बनर्जी सरकार की मुश्किल यह है कि वह अब यदि जोरदार तरीके से सिंगूर आंदोलन में अपनी भूमिका का बचाव करे तो निवेशक फिर भागेंगे। राज्य सरकार यदि इस मामले पर चुप्पी साधे रहेगी तब भी उद्योगपतियों के मन से संशय के बादल नहीं छंटेंगे। वैसे भी सिंगूर आंदोलन से तृणमूल कांग्रेस पल्ला इसलिए नहीं झाड़ सकती क्योंकि इसी की बदौलत वह वामपंथियों के दशकों पुराने शासन को उखाड़ कर सत्ता हासिल कर पाई थी। लेकिन उस आंदोलन की वजह से केवल औद्योगीकरण को ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा को भी गंभीर नुकसान पहुंचा था। यह एक सच्चाई है कि एक समय पश्चिम बंगाल देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में शुमार था लेकिन आज वह निवेश के लिए तरस रहा है। जहां तक टाटा मोटर्स के पक्ष में आये फैसले की बात है तो आपको बता दें कि टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा है कि तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक, कंपनी प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से 765.78 करोड़ रुपये की राशि 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूलने की हकदार है। ब्याज की गणना एक सितंबर, 2016 से मुआवजा चुकाने की तारीख तक होगी। टाटा मोटर्स ने सिंगूर संयंत्र बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से मुआवजा मांगा था। इसमें पूंजी निवेश पर हुए नुकसान समेत अन्य मदों में दावा किया गया था।

देखा जाये तो यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है लेकिन ग्लोबल बिजनेस समिट की तैयारियों में जुटी पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है और सत्तारुढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस ने टाटा मोटर्स की जीत को तवज्जो नहीं देते हुए कहा है कि यह ''अंतिम फैसला नहीं है'' तथा राज्य सरकार के सामने कानूनी रास्ते खुले हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता सरकार को यदि सरकारी खजाने से टाटा को 766 करोड़ रुपए देने पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी क्योंकि पहले ही गलत आर्थिक नीतियों के चलते राज्य का खजाना खाली बताया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करके कभी राजस्व बढ़ाने की दिशा में सही प्रयास ही नहीं किये। यह अलग बात है कि राज्य के मंत्रियों और विधायकों के यहां अक्सर पड़ने वाले छापों के दौरान जो करोड़ों रुपए मिलते हैं वह दर्शाते हैं कि राज्य में पैसे की कोई कमी नहीं है। आज के बंगाल की यह कड़वी सच्चाई है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोक लुभावन नीतियों की वजह से हो रही धन की बर्बादी के चलते राज्य पर कर्ज का भारी बोझ है। ऐसे में टाटा को 766 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश कैसे पूरा होगा यह सवाल सबके जेहन में आना स्वाभाविक है।

बहरहाल, सिंगूर के आंदोलन ने राज्य से निवेशकों को तो दूर किया ही था साथ ही टाटा मोटर्स का प्रोजेक्ट काफी हद तक लग जाने के चलते कृषि भूमि भी उपजाऊ नहीं रह गयी थी। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने सिंगूर के लोगों से विकास और रोजगार के जो वादे किये थे, बताया जाता है कि वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो बंगाल के हाथ से एक बड़ा प्रोजेक्ट गया था, कृषि भूमि बर्बाद हो गयी थी, किसानों को जमीन तो वापस मिल गयी लेकिन सुनहरा भविष्य नहीं मिला। अब 766 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य के खजाने पर पड़ गया है। कहा जा सकता है कि 2006 में ममता बनर्जी ने कोलकाता में एस्पलेनैड में 25 दिनों तक जो अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल की थी उसका विपरीत असर राज्य की आर्थिक सेहत पर लगातार देखने को मिल रहा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-30)

गतांक से आगे...

संकल्प और वासना की रस्सी से बंधा हुआ जीव दु:ख-जाल में फँसकर निरन्तर दुर्गति की ओर बढ़ता है। रेशम बनाने वाले कीड़े की तरह शक्तिमय चित् घनीभूत अहंभाव को प्राप्त करके स्वेच्छा से बन्धन में बँधता है। चित्शक्ति अपने ही द्वारा संकल्पित तन्मात्रा रूपी पाश में जकड़कर जंजीर से बँधे हुए सिंह के समान अत्यन्त लाचार हो जाती है।

इसी आत्मा को कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं अहंकार और कहीं चित्तरूप में जाना जाता है। यही कहीं प्रकृति और कहीं माया कहलाती है। कहीं बन्धन तो कहीं पुर्यष्टक (सूक्ष्मशरीर) कहा जाता है। इसे कहीं अविद्या और कहीं इच्छा नाम से जाना जाता है। यह आशा रूपी जाल का रचयिता सम्पूर्ण विश्व को वैसे ही धारण करता है, जैसे फलरहित वट का बीज वटवृक्ष को धारण करता है। यह मन चिन्तारूपी अग्निज्वाला से दग्ध हुआ, क्रोधरूपी अजगर द्वारा काटा गया और कामरूपी सागर के भँवर में फँसा हुआ है, यह अपने पितामह आत्मा को विस्मृत कर चुका है।

हे ब्रह्मन् ! कीचड़ (दल-दल) में फँसे हाथी के समान ही इस मन का उद्धार करो। जीव के आश्रित भाव ब्रह्म द्वारा लाखों; करोड़ों तथा असंख्य रूपों में कल्पित होकर पहले भी पैदा हो चुके हैं और आज भी पैदा हो रहे हैं तथा निर्झर से जलबिन्दुओं की उत्पत्ति के समान और भी उत्पन्न होते रहेंगे। कुछ प्रथम बार कुछ सौ से अधिक बार, कुछ असंख्य बार जन्म धारण कर चुके हैं और किन्हीं के तो दो-तीन ही जन्म हुए हैं। कोई किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर एवं नागरूप में उत्पन्न हैं। कोई सूर्य, चन्द्र, वरुण, हरि, शिव एवं ब्रह्मरूप धारण किये हुए हैं। कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आदि रूप में स्थित हैं। कोई औषधि, तृण, वृक्ष, फल, मूल एवं पत्ते के रूप में हैं तो कोई जम्बीर (नींबू), कदम्ब, आम, ताड़ तथा तमाल पेड़ के रूप में हैं। कुछ महेन्द्र, मलय, सह्य, मन्दर, मेरु आदि पर्वतों के रूप में विद्यमान हैं। कोई खारे सागर, कोई दूध, घृत, गन्ने के रस तथा जलराशि के रूप में स्थित हैं। कोई द्रुतवेग वाली नदियों के रूप में प्रवाहित हैं, तो कोई विस्तृत दिशाओं का रूप धारण किये हुए हैं।

कुछ ऊपर उठते हैं, कुछ नीचे गिरते हैं तथा कुछ पुन: ऊर्ध्वगमन करते हैं। हाथ से गेंद को बार-बार गिराने-उछालने के समान कुछ मृत्यु द्वारा ताड़ित होकर आसमान में उठते और गिरते रहते हैं। अनेक ऐसे हैं जो विवेकवान् होकर भी शुभकर्म करते और हजारों जन्म ग्रहण कर लेने पर भी उनका संसार सागर से आवागमन नहीं मिटता। दिशा और काल से अनवच्छिन्न आत्मतत्त्व जब अपनी सामर्थ्य से शरीर धारण करता है, तब यही जीव वासना के वशीभूत होकर संकल्पों की ओर जाने वाले चञ्चल मन का रूप ग्रहण कर लेता है।

क्रमश: ...

पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंडमुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

2 नवंबर, 2013 को माली में दो फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या के स्मरण में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। यूएन महासचिव ने स्वतंत्र प्रैस की महत्ता को रेखांकित किया जो उनके शब्दों में किसी लोकतंत्र की कार्यशीलता, ग़लत कार्यों का भांडा फोडने, हमारी जटिल दुनिया के संचालन, और टिकाऊ विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के कार्यों में अति महत्वपूर्ण है।

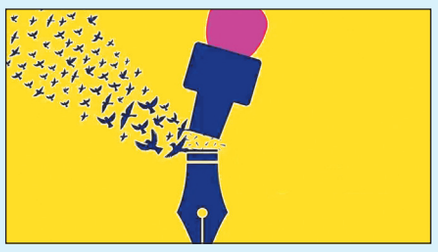

दुनिया भर में, पत्रकार अक्सर उन सभी मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम का सामना करते हैं जो सभी समाजों में व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। वे दुर्व्यवहारों और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालते हैं, अंतर-देशीय आपराधिक संगठनों द्वारा उठाए गए खतरों को उजागर करते हैं, और झूठे कथनों को फैलाने वाले प्रतिकूल जानकारी और प्रचार का पर्दाफाश करते हैं। ये प्रयास हमारे अपने लोकतंत्र के निरामय कामकाज में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं और दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करते हैं।

उनके पेशे के कारण, पत्रकारों को अक्सर उन लोगों से खतरा होता है जो उन्हें शांत करना चाहते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में, पत्रकारों के खिलाफ अपराध अदंडित ही रह जाते हैं। सीरिया में, स्थानीय और विदेशी पत्रकार दोनों पर ही नियमित रूप से हमले किये जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है जबकि वे संघर्ष पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वेनेजुएला में, सरकार मनमाने तरीके से मीडिया आउटलेट्स को तथ्यों की रिपोर्ट करने पर, या ऐसी संपादकीय लाइन को बनाए रखने, जो शासन की आलोचना करती हो, के लिए दंड के रूप में बंद कर देती है। सुरक्षा बल और हथियारबंद कोलाईटिवोस जिन्होंने इस साल की शुरुआत में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को परेशान और शारीरिक रूप से हमला किया, उन्हें अदंडित छोड़ दिया गया।

इराक में, मीडिया कर्मियों ने डराने, मौत की धमकी और उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट की। सूडान में, सरकार दंड से मुक्ति के साथ पत्रकारों को गिरफ्तारी, उत्पीड़न और धमकाने वाली है। यूगांडा में, सरकारी अधिकारियों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ उनकी दखलंदाज़ी को तेज कर दिया है, जिसमें पत्रकारों को धमकाया जाना शामिल है। नाइजीरिया और दक्षिणी सूडान में, पुलिस और अन्य अधिकारियों के लिए उत्तरदायित्व का कोई सबूत नहीं है जिन्होंने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लगातार तीसरे वर्ष, सोमालिया में पत्रकारों की अनसुलझी हत्याओं का दुनिया का सबसे खराब रिकॉर्ड है। रूस में, उच्च प्रोफाइल वाले पत्रकारों की हत्या के लिए किसी जवाबदेही की ओर प्रगति की कमी बनी हुई है।

टर्की में, पत्रकारों या स्वतंत्र मीडिया संस्थानों के खिलाफ हमलों करने वाले अपराधियों को अक्सर न्यूनतम दंड प्राप्त होता है। स्वतंत्र मीडिया को लक्षित करने के लिए न्यायिक प्रणाली के इस्तेमाल से इस दंड को बढ़ा दिया गया है। अज़रबैजान में, पत्रकारों के खिलाफ दस शारीरिक हमले में से नौ अनसुलझे रह जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अन्य लोगों के साथ, हम मीडिया पेशेवरों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए दंड मुक्ति को समाप्त करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशों में एक स्वतंत्र, पेशेवर और स्वतंत्र प्रेस को बढ़ावा देने के लिए, और उन लोगों की जवाबदेही का समर्थन करने के लिए अपने समर्पण को नवीनीकृत करती है जो खतरों, धमकियों और हिंसा के साथ मुक्त प्रेस को कमजोर करेगा।

इजरायल-हमास की लड़ाई में अल्लामा इकबाल की चर्चा

बिक्रम उपाध्याय

कोई सोच भी नहीं सकता है कि मौजूदा इजरायल-हमास की लड़ाई से मशहूर उर्दू शायर अल्लामा इक़बाल का भी कुछ लेना देना होगा। क्योंकि उनकी मृत्यु तो 1938 में ही हो चुकी थी। पर पाकिस्तान इस शायर को ग़ाज़ा पट्टी तक खींच लाया है। 30 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान के मुख्य अख़बार डॉन ने मौजूदा इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में अल्लामा इक़बाल को उद्धृत करते हुए एक बड़ा लेख छापा है, जिसमें कहा गया है कि इकबाल फिलिस्तीनियों के हक़ के प्रति इतने आग्रही थे कि उन्होंने यहां तक कहा था कि यदि यहूदियों का हक़ फिलिस्तीन की जमीन पर है तो फिर अरबों का भी हक़ स्पेन पर होना चाहिए क्योंकि वे वहीं से आए थे।

डॉन में यह लेख रऊफ पारेख ने लिखा है। पारेख एक उर्दू कोशकार, भाषाविद् और अखबार के स्तंभकार हैं। वह लिखते हैं कि अल्लामा इक़बाल फ़िलिस्तीनी मुद्दे के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने तब यहूदी राष्ट्र इजरायल के बनने का विरोध किया था जब फ़िलिस्तीन के एक हिस्से को यहूदियों को देने का अंग्रेज़ों ने इरादा जताया था। रऊफ पारेख ने दावा किया है कि ज़र्ब-ए-कलीम में शामिल अपनी कविता शाम-ओ-फलस्तीन में, अल्लामा इक़बाल कहते हैं– है ख़ाक-ए-फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पे हक नहीं क्यों अहल-ए-अरब का? यानी यदि यहूदियों का फ़िलिस्तीन की धरती पर अधिकार है, तो अरबों का स्पेन पर अधिकार क्यों नहीं है? इस शेर को समझाते हुए पाकिस्तानी लेखक यह कहता है कि इकबाल की नज़र में फ़िलिस्तीन सिर्फ अरबों का है, और यदि कोई इस आधार पर फ़िलिस्तीन की भूमि पर यहूदियों के अधिकारों की वकालत करता है कि फ़िलिस्तीन से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, तो अरबों को भी स्पेन से निर्वासित कर दिया गया था, फिर उनका हक़

स्पेन पर क्यों ना हो।

रउफ पारेख कहते हैं कि इक़बाल को फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के प्रति गहरी सहानुभूति थी, क्योंकि उनका मानना था कि इस्लाम सभी नस्लों, क्षेत्रों और सीमाओं से परे है। हालांकि इकबाल की मृत्यु इजरायल बनने से पहले 1938 में ही हो गई थी, लेकिन यहूदी राष्ट्र इजरायल बनाने की मांग उनके जीवन काल में ही उठने लगी थी। लेखक का दावा है कि इकबाल मध्य पूर्व के घटनाक्रम पर करीब से नज़र रख रहे थे। पश्चिमी देश बातचीत के दौरान किए गए सभी वादों को कुचलते हुए फिलिस्तीन में यहूदियों को जमीन देने पर आमादा थे। एक और पाकिस्तानी शायर बशीर अहमद डार ने अपनी पुस्तक अनवर-ए-इकबाल में लिखा है कि 30 दिसंबर, 1919 को लाहौर के प्रसिद्ध मोची गेट के बाहर एक सार्वजनिक रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में इकबाल ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मांग की गई कि ब्रिटिश सरकार ने मध्य पूर्व में उनके क्षेत्रों के संबंध में जो मुसलमानों से वादे किए थे, पहले उनको पूरा किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी मुस्लिम भूमि का कोई भी हिस्सा किसी अन्य पक्ष को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

रउफ पारेख आगे लिखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमानों को जो कुछ दिया गया, उससे इकबाल पूरी तरह निराश थे। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस को कफन दुजदे चांद या कब्रों से कफन चुराने वाले लोगों के रूप में सम्बोधित किया था। उन्होंने तब कहा था कि कब्रें बांटने के लिए एक लीग बनाई गई है। इकबाल के अनुसार अपने शासन के दौरान ओटोमन तुर्कों ने यहूदियों के प्रति बहुत उदार और सहिष्णु रवैया दिखाया था। उन्होंने यहूदियों को पश्चिमी दीवार के सामने प्रार्थना करने की अनुमति दी, जो यरूशलेम में डोम ऑफ रॉक के निकट स्थित एक प्राचीन दीवार थी और मुसलमानों के बीच बुराक दीवार के रूप में जानी जाती थी।

इकबाल ने सितंबर 1929 में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई यहूदी समर्थक नीतियों की आलोचना करते हुए एक भाषण दिया था। जिसके अंश को मुहम्मद रफीक अफजल ने अपनी पुस्तक गुफ्तार-ए-इकबाल में उद्धृत किया है। इक़बाल के अनुसार तुर्क यहूदियों के प्रति असाधारण सहिष्णु रवैया दिखा रहे हैं। इस्लामिक शरिया के अनुसार अल-अक्सा मस्जिद का पूरा कोर्ट क्षेत्र वक्फ (या बंदोबस्ती) है। यहूदी इसके नियंत्रण और उपयोग का दावा करते हैं लेकिन कानूनी और ऐतिहासिक रूप से उनका इस पर कोई अधिकार नहीं है।

राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था और अंग्रेज यहूदियों का समर्थन कर रहे थे। तो इक़बाल ने अपनी कविता ज़र्ब-ए-कलीम में तंज करते हुए लिखा – तेरी दावा न जिनेवा में है न लंदन में, फरंग की राग-ए-जान पंजा-ए-यहूद में है। इस शेर में इकबाल फिलीस्तीनी अरबों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आपका हिमायती न तो जिनेवा में हैं और न ही लंदन में क्योंकि पश्चिम के गले की नस यहूदियों के चंगुल में है।

डॉन में छपे लेख के अनुसार एक और कलमनिगार मुहम्मद हमजा फारूकी ने अपने एक लेख में उल्लेख किया है कि अल्लामा इकबाल 1931 के आखिरी कुछ महीनों के दौरान लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अधिक स्वशासन के सुधारों पर चर्चा करने गए थे। उन्हीं दिनों, विश्व मुस्लिम कांग्रेस द्वारा ज़ायोनिस्ट खतरे पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन येरुशलम में भी हो रहा था। इक़बाल लंदन का सम्मेलन छोड़कर येरुशलम सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गये थे। अल्लामा इक़बाल ने 7 अक्टूबर,1937 को मुहम्मद अली जिन्ना को पत्र लिखकर इजरायल को लेकर पूरी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि फिलिस्तीन का प्रश्न मुसलमानों के दिमाग को बहुत परेशान कर रहा है।

इक़बाल वे शायर थे जिन्होंने एक तरफ तो लिखा था सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना को अलग पाकिस्तान बनाने के लिए उकसाया था। अल्लामा इक़बाल ने ही भारत के मुसलमानों की एक अलग पहचान और उस पहचान की रक्षा के लिए एक अलग मातृभूमि की स्थापना की मांग को सबसे पहले उठाया था। 28 मार्च 1909 को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी की स्थापना के विचार को अस्वीकार करते हुए कहा था – अब मैंने यह मानना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्रीय पहचान उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

1930 में, इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्र में इकबाल ने कहा था – भारत अलग-अलग नस्लों से संबंधित, अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग-अलग धर्मों को मानने वाले मानव समूहों का एक महाद्वीप है। उनका व्यवहार किसी भी तरह से सामान्य नस्ल चेतना से निर्धारित नहीं होता है। इसलिए, मैं उनके सर्वोत्तम हित में एक समेकित मुस्लिम राज्य के गठन की मांग करता हूं।

हिन्द स्वराज्य

छुटकारा (भाग-2)

गतांक से आगे...

प्रश्न– इतना तो आप दोनों पक्षों से कहेंगे। परन्तु अंग्रेजों से क्या कहेंगे?

उत्तर– उनसे मैं विनय से कहूंगा कि आप हमारे राजा जरूर हैं। आप अपनी तलवार से हमारे राजा हैं या हमारी इच्छा से, इस सवाल की चर्चा मुझे करने की जरूरत नहीं। आप हमारे देश में रहें इसका भी मुझे द्वेष नहीं है। लेकिन राजा होते हुए भी आपको हमारे नौकर बनकर रहना होगा। आपका कहा हमें नहीं, बल्कि हमारा कहा आपको करना होगा। आज तक आप इस देश से जो धन ले गये, वह भले आपने हजम कर लिया। लेकिन अब आगे आपका ऐसा करना हमें पसन्द नहीं होगा। आप हिन्दुस्तान में सिपाहगिरी करना चाहें तो रह सकते हैं। हमारे साथ व्यापार करने का लालच आपको छोड़ना होगा। जिस सभ्यता की आप हिमायत करते हैं उसे हम नुकसानदेह मानते हैं। अपनी सभ्यता को हम आपको सभ्यता से कहीं ज्यादा ऊँची समझते हैं। आपको भी ऐसा लगे तो उसमें आपका लाभ ही है। लेकिन ऐसा न लगे तो भी आपको, आपकी ही कहावत के मुताबिक, हमारे देश में हिन्दुस्तानी होकर रहना होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे धर्म को बाधा पहुँचे। राजकर्ता होने के नाते आपका फर्ज है कि हिन्दुओं की भावना का आदर करने के लिए आप गाय का मांस खाना छोड़ दें और मुसलमानों के खातिर बुरे जानवर (सूअर का मांस खाना छोड़ दें। हम दब गये थे इसलिए बोल नहीं सके, लेकिन आप ऐसा न समझें कि आपके इस बरताव से हमारी भावनाओं को चोट नहीं पहुँची है। हम स्वार्थ या दूसरे भय से आजतक कह नहीं सके, लेकिन अब यह कहना हमारा फर्ज हो गया है। हम मानते हैं कि आपकी कायम की हुई शालाएँ और अदालतें हमारे किसी काम की नहीं हैं। उनके बजाय हमारी पुरानी असली शालाएँ और अदालतें ही हमें चाहिए। हिन्दुस्तान की आम भाषा अंग्रेजी नहीं, बल्कि हिन्दी है। वह आपको सीखनी होगी और हम तो आपके साथ अपनी भाषा में ही व्यवहार करेंगे। आप रेलवे और फौज के लिए बेशुमार रुपये खर्च करते हैं, यह हमसे देखा नहीं जाता। हमें उसकी जरूरत नहीं मालूम होती। रूस का डर आपको होगा, हमें नहीं है। रूसी आयेंगे तब हम उनसे निबट लेंगे; आप होगे तो हम दोनों मिलकर उनसे निबट लेंगे। हमें विलायती या यूरोपी कपड़ा नहीं चाहिए। इस देशमें पैदा होनेवाली चीजोंसे ही हम अपना काम चला लेंगे।

क्रमश: ...

तुष्टिकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रहे कुछ राजनीतिक दल

योगेंद्र योगी

इज़रायल-फिलिस्तीन युद्ध में हमास के क्रूर आतंकी घटना की आलोचना करने की बजाए इजरायल की निंदा करने से साबित हो गया है कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अल्पसंख्यकों के वोट के लिए किस तरह तुष्टिकरण की नीति पर चलते हैं। यही वजह है कि भाजपा विपक्षी दलों पर आक्रामक रुख अख्तियार करती रही है। दरअसल विपक्षी दल आतंकी हमास की निंदा करके देश के अल्पसंख्यक वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। इस नए युद्ध की शुरुआत आतंकी संगठन हमास ने की। इसमें सैंकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोगों का अपहरण कर लिया। इसके विपरीत इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति अपना कर भाजपा को फिर से एक नया मुद्दा थमा दिया।

केंद्र की भाजपा सरकार ने पहले दिन से ही रुख साफ कर दिया कि किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई का भारत समर्थन नहीं करेगा। केन्द्र सरकार की यह नीति जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली आतंकी कार्रवाईयों से प्रभावित है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में नये बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस को छोड़ कर ज्यादातर दलों ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। ऐसे मुद्दों पर विपक्षी दल ज्यादातर बचाव या विरोध की नीति ही अपनाते रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सहित गैर भाजपा दलों का निशाना भी अल्पसंख्यक वोट बैंक होता है। ऐसे में कोई भी दल सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया जाहिर करने से बचता है। इसमें हमास ने पहले हमला कर युद्ध को आमंत्रित किया, इसलिए विपक्षी दल स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से कतरा रहे हैं। इसके विपरीत जम्मू-कश्मीर में धारा 370, तीन तलाक और अयोध्या में राम मंदिर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करने में देर नहीं लगाई। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर की शांति और तरक्की की हालत सर्वविदित हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग शून्य हो गई हैं। इस साल पर्यटकों की

रिकार्ड आमद दर्ज की गई है। जम्मू-कश्मीर से एक अग्निवीर का दस्ता तक सेना में शामिल हुआ है। जम्मू-कश्मीर में जी20 की बैठक हो चुकी है। इसी से स्पष्ट होता है कि गैरभाजपा दलों को किस तरह से अल्पसंख्यक वोट बैंक के तौर पर नजर आते हैं।

इज़रायल-फिलिस्तीन युद्ध पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर फिलिस्तीन के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें निराशा और पीड़ा व्यक्त की और फिलिस्तीनी लोगों के भूमि (और) स्वशासन, गरिमा और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के प्रति अपने समर्थन को तवज्जों दी। हमास ने जिस तरह बच्चों और महिलाओं के कत्ल करके इंसानियत को शर्मसार किया, उस पर कांग्रेस ने एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही अपहृत लोगों को रिहा किए जाने की अपील की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी का हमेशा मानना रहा है कि इजरायलियों की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को सुनिश्चित करते हुए फिलिस्तीन के लोगों की वैध आकांक्षाओं को बातचीत के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस के इस बयान पर भाजपा ने जोरदार हमला बोला।

भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक पोस्ट में कांग्रेस के बयान को अत्यंत निंदनीय बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर राष्ट्रनीति और राष्ट्रहित के खिलाफ फैसला लेते हुए प्रस्ताव पारित किया है। एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस किस हद तक गिर सकती है? उन्होंने कहा, अब कांग्रेस आतंकवाद से भी समझौता करने को तैयार है। हम और हमारी पार्टी भी विपक्ष में रही हैं लेकिन कभी भी राष्ट्रहित के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ है। अपने प्रस्ताव में कांग्रेस ने कहा कि सीडब्ल्यूसी मध्य पूर्व में छिड़े युद्ध पर अपनी निराशा और पीड़ा व्यक्त करती है, जहां पिछले दो दिनों में एक हजार से अधिक लोग मारे गए हैं।

भाजपा ने हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस के शासन के दौरान हुई आतंकी वारदातों को गिना दिया। इसका एक वीडियो जारी करते हुए भाजपा ने कहा कि यूपीए के समय जून 2004 से मई 2014 तक भारत में 10, 262 आतंकी हमले हुए। जिसमें 7012 नागरिकों की जान गई। 2014 में देश में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। जिसके बाद 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इजराइल और हमास से जुड़े युद्ध के बीच कांग्रेस के प्रस्ताव की तुलना पाकिस्तान और तालिबान से की और आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश के हित का बलिदान करना उसके डीएनए में है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के प्रस्ताव में पाकिस्तान और तालिबान के बयानों से काफी समानताएं हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस, पाकिस्तान और तालिबान हमास की निंदा नहीं करते। इजराइल पर आतंकवादी हमले की निंदा नहीं करते और बंधक महिलाओं और बच्चों के संबंध में चुप हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देशहित की बलि चढ़ाना कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस बेशक फिलीस्तीन की दुहाई की आड़ में हमास की आतंकी कार्रवाई की निंदा से बेशक बच रही हो किन्तु खाड़ी के कुछ देशों ने इसकी भर्त्सना की है।

यूएई के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा था कि वो इसराइली नागरिकों को उनके घरों से अगवा कर के बंदी बनाए जाने की ख़बरों से स्तब्ध है। बहरीन ने भी हमास के हमलों की आलोचना की है। बहरीन ने कहा था कि हमले ने तनाव को ख़तरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। इन दोनों देशों के ये बयान उनके पहले के रुख़ से अलग है, जब पूरा अरब वर्ल्ड इसराइल के खिलाफ एक सुर में बोलता था। ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है और इसराइल पर सीधे उंगली उठा रहा है। ईरान के हितों का अपना समीकरण है और उसी के हिसाब से वह प्रतिक्रिया दे रहा है। क़तर ने इसराइल को इस तनाव का अकेला जिम्मेदार बताया है। मलेशिया, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान ने भी फ़िलस्तीनियों के प्रति समर्थन दिखाया है। खाड़ी देशों के इस तरह अलग-अलग बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व में देशों के रिश्ते किस तरह बदल रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस सहित भारत के विपक्षी दल अभी तक ऐसे मसलों को सिर्फ वोट बैंक से नजरिए से देखते रहे हैं। भारत के संबंध खाड़ी देशों से लगातार बेहतर हो रहे हैं।

गौरतलब है कि हमास के हमले से पहले सऊदी अरब और दूसरे देश इसराइल से संबंध सुधारने के लिए समझौता करने वाले थे। इस हमले के बाद हालात बदल गए हैं। इस हमले की वजह भी यही मानी जा रही है कि किसी तरह इन देशों में कोई समझौता नहीं होने पाए। कांग्रेस और विपक्षी दल इंडिया की तीन बैठकों में अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि घरेलू और विदेशी मसलों पर नीति क्या रहेगी। इसी तरह भ्रष्टाचार और दूसरों मुद्दों पर भी विपक्षी गठबंधन की एकराय नहीं हो सकी। यह विपक्षी दलों की ढुलमुल नीति का ही परिणाम है कि भाजपा इन मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लेने में पीछे नहीं रही। देश और विदेश हितों से जुड़े भारत के मुद्दों पर राय कायम करने से पहले विपक्षी गठबंधन के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती चुनाव में सीट शेयरिंग की है। इस अधरझूल एजेंडे के कारण ही विपक्षी एकता सिरे नहीं चढ़ सकी है। विपक्षी गठबंधन में पारदर्शिता और स्पष्टता नहीं रही तो लोकसभा चुनाव में भाजपा की चुनौती का एकजुट होकर सामना करना आसान नहीं होगा।

राजस्थान के योगी को जिताने यूपी के योगी उतरे मैदान में

राहुल संपाल

राजस्थान में भाजपा की दो और कांग्रेस की पांच लिस्ट अब तक आ गई हैं। कई सीटों पर रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक सीट अलवर की तिजारा विधानसभा है। यहां भाजपा ने अपने फायरब्रांड नेता और सांसद बाबा बालकनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। बालकनाथ अपने समर्थकों के बीच राजस्थान के योगी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से भी चौथी लिस्ट में इस सीट पर पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर इमरान खान को उतारा है। दिलचस्प बात है कि इमरान खान को पहले बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन अचानक से इस सीट पर बसपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। जैसे ही बसपा ने टिकट बदला वैसे ही कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में इमरान खान को तिजारा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। दरअसल, इमरान खान जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। मेवात इलाके में इमरान की मजबूत पकड़ बताई जा रही है। उनकी सियासी मज़बूती को ध्यान रखते हुए कांग्रेस ने इमरान को तिजारा से टिकट दिया है। जानकारों का कहना है कि मायावती और बीएसपी के नेताओं को यह जानकारी भी मिल रही थी कि इमरान कांग्रेस के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ मायावती के सियासी विरोधी उन पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि वह पैसे लेकर टिकट देती हैं, इस वजह से इमरान से टिकट वापस लिया गया। 2018 और 2013 के विधानसभा चुनावों को देखें तो कांग्रेस को यहां हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस की ओर से इस सीट पर बार-बार प्रयोग किए जाते रहे हैं। यहां दुर्रू मियां का टिकट कांग्रेस काट चुकी है। वहीं बसपा से कांग्रेस में आए विधायक संदीप का टिकट काटकर भी अब कांग्रेस ने यहां नया प्रयोग किया है। साल 2018 में संदीप यहां बसपा की टिकट से जीते थे। इससे पहले 2013 में मामन सिंह यादव ने इस सीट से जीत दर्ज की थी, जो भाजपा की ओर से टिकट न दिए जाने की वजह से नाराज हैं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है। इधर इस सीट से तिजारा से भाजपा प्रत्याशी सांसद बालकनाथ 1 नवंबर को पर्चा दाखिल किया। बालकनाथ के नामांकन के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्य नाथ भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ यहां बुधवार को एक जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ मस्तनाथ मठ के महंत हैं। इसी कारण उनकी ड्रैसिंग स्टाइल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह दिखती है। इसलिए उनको राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बालक नाथ को भाजपा के फायरब्रांड नेताओं में से एक माना जाता है। वह हिंदुत्व एजेंडे पर अपने आक्रामक रुख के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। अपनी फायर ब्रांड वाली छवि के चलते वह आमजन में काफी प्रसिद्ध हैं। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में महंत बाबा बालकनाथ योगी अलवर से सांसद चुने गए थे। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को शिकस्त दी। बाबा बालकनाथ मस्तनाथ मठ के आठवें महंत हैं, जिन्हें महंत चांद नाथ योगी ने 2013 में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तब ही से वह राजनीति में खुद को आजमा रहे हैं।

जनता की सक्रियता से ही साफ-सुथरी होगी राजनीति

विश्वनाथ सचदेव

जब कोई राजनेता कुछ करने का आश्वासन दे तो इसका अर्थ है कि या तो वह आपको मूर्ख समझता है या मूर्ख बना रहा है। रूसी नेता निकिता ख्रुश्चेव ने एक बार कहा था, सब राजनेता एक से होते हैं, वे वहां भी पुल बनाने का आश्वासन दे सकते हैं, जहां नदी ही न हो। रूसी नेता ने शायद यह बात अपने देश के संदर्भ में कही हो, पर यह बात हमारे देश पर भी लागू होती है। आश्वासन, दावे, वादे आज हमारी राजनीति का एक अविभाज्य हिस्सा बन गए हैं और चुनावी मौसम में तो इन सबकी भरमार हो जाती है। न कोई नेता यह बताता है कि उसके पिछले वादों का क्या हुआ और न मतदाता यह पूछने की जरूरत समझता है कि पिछले वादे पूरे क्यों नहीं हुए और उनके वादों-आश्वासनों पर क्यों विश्वास किया जाए। पर शायद राजनेता यह समझने लगे हैं कि मतदाता में उनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। जोर से बोलने की इस प्रतिस्पर्धा में कोई नेता पीछे नहीं रहना चाहता। वह यह मानकर चल रहा है कि जैसे पिछले आश्वासनों को आम जनता भूलती रही है, वैसे ही आगे भी भूल जाएगी। पर सवाल आश्वासनों को याद रखने और भूलने का नहीं है, सवाल हमारी समूची राजनीति पर लगातार लग रहे सवालिया निशानों का है। हमारी समूची राजनीति आज कठघरे में है, हमसे जवाब मांग रही है कि हमने उसे यानी राजनीति को नेताओं के भरोसे ही क्यों छोड़ दिया है? हर पार्टी का हर नेता सिद्धांतों और मूल्यों की दुहाई देता है, अपनी कमीज को दूसरे की कमीज से उजली बताने के दावे करता है। हकीकत यह है कि हमारी आज की राजनीति का सिद्धांतों-मूल्यों से कोई रिश्ता नहीं रह गया, और हकीकत यह भी है की सारी कमीजें मैली हैं। हमारी राजनीति का यह हाल इसलिए हो गया है कि हमने इसे राजनेताओं के भरोसे छोड़ दिया-उन राजनेताओं के जिन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं रहती कि कल उन्होंने क्या बोला था, और आज क्या कह रहे हैं! कल जिस बात को गलत ठहरा रहे थे, आज वही बात उन्हें सही लगने लगती है। अब समय आ गया है कि जनता राजनेताओं के हाथों का खिलौना बने रहने से इंकार करे। जनतंत्र का मतलब पांच साल में एक बार वोट मांगना या वोट देना ही नहीं होता। जनतंत्र एक जीवन-प्रणाली है। राजनीतिक ईमानदारी इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। यह ईमानदारी कहीं खो गई है। नहीं, खोई नहीं है, हम जानबूझकर इस चाबी को कहीं रख कर भूल गए हैं। जनता को यह चाबी अपने हाथ में लेनी ही होगी। हमें अपने नेताओं से पूछना ही होगा कि उनकी कार्य-प्रणाली में ईमानदारी के लिए कोई जगह क्यों नहीं है? सिद्धांतों, मूल्यों और नीतियों के आधार पर राजनीतिक दल क्यों नहीं बनाए और चलाए जा सकते?

जानबूझ कर भ्रम पैदा करते हैं नीतीश

बिक्रम उपाध्याय

पिछले दिनों बिहार के मोतीहारी में 2014 में केंद्रीय विश्वविद्यालय देने के लिए एनडीए की सरकार को साधुवाद और भाजपा के कुछ नेताओं को पुराने मित्र कह कर एक बार फिर नीतीश कुमार ने इस चर्चा को गर्म कर दिया कि कहीं वह भाजपा के साथ फिर से आने की तो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन नीतीश को जानने वाले इस तरह की बातों को अब तव्वजो नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बिहार के मुख्यमंत्री अपने बारे में चर्चा करवाने के लिए खूब जाने जाते हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बार यूं ही नहीं कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है।

2005 से लेकर आज तक नीतीश की कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि वह अपनी पार्टी के दम पर सरकार बनाने या बनाये रहने की ताकत रखते हों। हर बार उन्हें किसी न किसी बैसाखी की जरूरत पड़ी। पर उनकी कौशलता या बिहार की राजनीति की मजबूरी कहें कि 2005 से लेकर आज तक, सिवाय इसके कि कुछ महीनों के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कमान दी गई, नीतीश कुमार ही लगातार सरकार का नेतृत्व करते आए हैं। हां बारी बारी से उन्होंने सहयोगी जरूर बदले हैं। लगभग 19 साल में वह आठ बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसी के साथ भी स्थाई दोस्ती या दुश्मनी कभी नहीं की।

अभी तक के अपने राजनीतिक जीवन में नीतीश को इतनी उलझन कभी नहीं रही, जितनी इस समय है। उन्होंने विपक्ष को एक सूत्र में बांधने की पहल तो की, लेकिन इसका नेतृत्व उन्हें मिलेगा इसको लेकर वह जरा भी आश्वस्त नहीं है। कई बार वह खुद भी इस पर बयान दे चुके हैं कि उनका मकसद इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना बिल्कुल नहीं है। उनके संयोजक बनने में बाधा भी बिहार

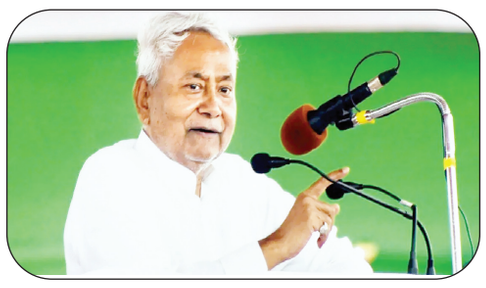

से ही खड़ी हुई, जब राहुल गांधी को अपने करीब पा कर राजद प्रमुख लालू यादव ने यह बयान दे दिया कि इंडिया गठबंधन का एक नहीं कई संयोजक हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन भी ठंडा पड़ा हुआ है। बल्कि आपसी तकरार में घुस गया है। कांग्रेस को लेकर सपा और आम आदमी पार्टी काफी नकारात्मक और अग्रेसिव व्यवहार कर रहे हैं। जाहिर है इसे ठंडा करने का दायित्व कम से कम नीतीश कुमार को किसी ने नहीं दिया है।

नीतीश को बिहार में ही बहुत सारी चुनौतियां झेलनी पड़ रही है। खास कर सरकार चलाने के नीतीश के तरीके से राजद के लोग कसमसा रहे हैं। ना तो केबिनेट का विस्तार हो पा रहा है और ना सीटों के गठबंधन को लेकर ही कोई विचार विमर्श शुरू हुआ है। राजद और नीतीश की पार्टी के नेता एक दूसरे के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सतर्क निगाहों से एक दूसरे की गातिविधियां देख रहे हैं। कई फैसले ऐसे हैं जिनको लेकर राजद नेताओं में नाराजगी भी है। नाराज तो कांग्रेस भी है। गठबंधन में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस के विधायकों को उनके कोटे के अनुसार मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। अभी बिहार में सिर्फ दो कांग्रेस विधायकों को ही मंत्री पद मिला है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि उनके कोटे में चार मंत्री का वायदा किया गया था। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह खुलेआम कह चुके हैं कि मौजूदा बिहार सरकार में कांग्रेस की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नीतीश को मालूम है कि बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले ही उनका और उनकी पार्टी जनता दल यू के भाग्य का फैसला हो जाएगा। क्योंकि लोक सभा के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन ही बिहार विधान सभा के चुनाव की दिशा तय करेगा। पर उसके लिए जरूरी है कि लोक सभा की अधिकतम सीटों पर नीतीश अपनी पार्टी के लोगों को जिता सकें। मौजूदा लोकसभा में जदयू के 16 सांसद हैं और इंडिया गठबंधन में 28 राजनीतिक पार्टियां हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू, भाकपा और माकपा बिहार में टिकटों की प्रबल दावेदार पार्टियों में है। आम आदमी पार्टी इस समय राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के साथ देशव्यापी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में जनता दल यू को 16 ससंदीय सीटें मिल ही जाएंगी, यही सुनिश्चित नहीं है। कम से कम आपसी सहयोग के आधार पर तो यह संभव नहीं लगता। बिहार का कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जहां राजद और जदयू के उम्मीदवार अलग अलग लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश के पास सिवाय इसके कि वह राजद को अपने बारे में सशंकित रखें, कोई अन्य उपाय नहीं है।

नीतीश के लिए सबसे बड़ा खतरा अपने लोगों से ही है। जदयू के भीतर काफी घुटन है। ना सिर्फ अपने भविष्य को लेकर जदयू के नेता आशंकित हैं, बल्कि पार्टी के अस्तित्व पर ही उनके मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जदयू के नेताओं के साथ नजदीक का संपर्क ही नहीं है। उनके खेमे के कुछ नेताओं को ही उनके निकट जाने का अवसर मिल पाता है, बाकी नेताओं के लिए उनका व्यवहार भी मधुरता का नहीं है। ऐसे में यदि नीतीश इसी नेतृत्व के साथ आगे चलने का फैसला बरकरार रखते हैं तो पार्टी में कभी भी विद्रोह हो सकता है।

सीबीआई और ईडी की लगाम कौन कसे ?

अजय सेतिया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। पहले जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में अपने एक मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंत्री पद से हटाना पड़ा था, वहीं अब राशन वितरण घोटाले में पूर्व खाद्य मंत्री और मौजूदा वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। एक दिन पहले जब ईडी के अधिकारी ज्योतिप्रिय मलिक के घर पर छापा मारने के बाद उन्हें साथ ले गए थे, तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के दुरूपयोग का आरोप लगाया था।

पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के समय ममता बनर्जी उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटाने को मजबूर हो गई थीं क्योंकि पार्थ की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 22 करोड़ रूपए और एक अन्य सहयोगी के घर 28 करोड़ बरामद किए थे। दो साल पहले नारदा स्टिंग मामले में भी ममता सरकार के दो मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम को भी गिरफ्तार किया था। जब इन दोनों मंत्रियों और एक विधायक को गिरफ्तार किया गया था, तो ममता बनर्जी ने कोलकात्ता के सीबीआई दफ्तर के सामने धरना दे दिया था। तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े और बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल को मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र में जब महाविकास अघाड़ी सरकार थी, तो उसके दो मंत्रियों अनिल देशमुख और नवाब मलिक को भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया था। दोनों उद्धव ठाकरे की सरकार में शरद पवार की एनसीपी कोटे के मंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया था।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में और जेल मंत्री सत्येन्द्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबे समय से जेल में हैं। मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया, तो मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सत्येन्द्र जैन का भी इस्तीफा लेना पड़ा, जो जेल मंत्री होते हुए साल भर से जेल में थे। आम आदमी पार्टी के सासंद संजय सिंह भी शराब घोटाले में जेल में हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में चार्जशीटेड हैं। यह तब का मामला है जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर रिहा हैं। क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में घोटाले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 2020 में ईडी ने उनकी 11.86 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क कर ली थी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल, सोनिया गांधी की कांग्रेस और फारूख अब्दुला की नेशनल कांफ्रेंस सभी छह दल इंडी एलायंस के मुख्य घटक हैं। इसलिए 26 अक्टूबर को बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के घर पर राशन वितरण घोटाले में और

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के घर पर पेपर लीक घोटाले में ईडी ने छापे मारे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर अपने विरोधियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसियों के दुरूपयोग का आरोप लगाया।

अशोक गहलोत इस बात से आग बबूला हो गए कि उनके बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने सम्मन भेजा है। असल में सांसद किरोड़ी लाल मीना ने अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ईडी को एक शिकायत भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि काले धन को सफेद करने के लिए वैभव गहलोत की कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडी एलायंस में एकता का प्रदर्शन करने के लिए एलायंस के लगभग सभी दलों ने भी ममता बनर्जी और गहलोत जैसे बयान दिए हैं। विपक्ष पिछले कई सालों से आरोप लगाता रहा है कि जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सीबीआई और ईडी ने विरोधी दलों को निशाना बनाया हुआ है। इस संबंध में आंकड़े भी बताए जाते हैं कि 2014 के बाद नेताओं के खिलाफ़ ईडी के इस्तेमाल में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। यह भी कि जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनमें से 95 प्रतिशत विपक्ष के नेता हैं। इंडी एलायंस बनाने से पहले 13 राजनीतिक दलों में इस बात पर सहमति हुई थी कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर रही केन्द्रीय एजेंसियों का मिलजुल कर मुकाबला करना चाहिए। इसलिए 24 मार्च को इन 13 दलों की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया था कि जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, ईडी और सीबीआई ने जितने नेताओं पर कार्रवाई की है, उनमें से 95 प्रतिशत मामले विपक्षी दलों के नेताओं से संबंधित हैं।

याचिका में मांग यह थी कि इन एजेंसियों को गाईड लाईन जारी की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार उनका राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। याचिका में बताया गया था कि 2004 से 2014 के बीच 72 राजनेताओं के खिलाफ सीबीआई ने जांच की थी। जिनमें से 60 प्रतिशत से भी कम (43) विपक्षी पार्टियों से संबंधित थे। लेकिन मोदी सरकार में यह आंकड़ा 95 प्रतिशत के पार जा चुका है। विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट में कहा कि ईडी की रेड एक प्रताड़ना के टूल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2013-2014 में 209 केस रजिस्टर्ड थे, 2020-21 में इनकी संख्या 981 हो गई थी और 2021-22 में 1180 पहुंच गई। मजेदार बात यह है कि इस याचिका में यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता विपक्षी पार्टियों को भी 45 प्रतिशत वोट मिले थे। यह बड़ी बेतुकी याचिका थी, जिसे सुप्रीमकोर्ट ने पहली ही सुनवाई में खारिज कर दिया था। अब जब चुनावों से पहले ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई तेज की है, तो विपक्ष में हड़कंप कुछ ज्यादा है। वे मोदी पर हमलावर हो रहे हैं, सभी विपक्षी दलों ने इन दोनों एजेंसियों के राजनीतिक दुरूपयोग के फिर आरोप लगाए हैं। सुप्रीमकोर्ट में वे मात खा चुके हैं, अब वे चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि चुनावों के दौरान सीबीआई ईडी के हाथ पांव बांधे जा सकें।

अशोक गहलोत ने तो यहां तक कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं, वहां वहां ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। यह चुनाव आयोग में दस्तक देने का संकेत है। लेकिन चुनाव आयोग के पास ऐसी ताकत ही नहीं कि वह केन्द्रीय जांच एजेंसियों पर कोई पाबंदी लगा सके। दूसरी तरफ सरकार के बचाव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि ईडी ने 9 साल में 5,906 केस रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें सिर्फ 3 प्रतिशत केस ही राजनीतिक लोगों से संबंधित हैं। इसलिए यह कहना आधारहीन है कि ईडी सिर्फ राजनीतिक लोगों पर ही कार्रवाई करती है। शेखावत ने अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस बात का दोषारोपण करते हैं कि ईडी की कार्रवाई उन्हीं प्रदेशों में होती है जहां चुनाव होने वाले हैं और विपक्षी नेताओं को टारगेट करके ईडी की कार्रवाई की जाती है तो उन्हें यह बताना चाहिए कि अब से पहले जितने ईडी के मामले हुए हैं, उनमें से कितनी कार्रवाई में अदालत से राहत मिली है? अगर सरकार के प्रभाव में एजेंसी ने काम किया होता, तो निश्चित तौर पर अदालत ने हस्तक्षेप कर ऐसे नेताओं को राहत प्रदान की होती।

कांग्रेस टिकट की दौड़ में आशा और वेदांती के बीच कांटे का मुकाबला

संगीता, अंबिका, कमलाकांत और अनिल हुए पीछे

बैकुण्ठपुर वि0स0 सीट में कांग्रेस से टिकिट को लेकर लगातार असंमजस की स्थिति बनी हुई है । विभिन्न प्रचार माध्यमों में वेदांती तिवारी का नाम अंतिम सूची में होने की खबर को भी विराम लग गया जब ए0आई0सी0सी0 द्वारा जारी सूची में 07 वि0स0 क्षेत्रो के टिकिट दावेदारी को फाईनल नहीं किया गया जिसमें बैकुण्ठपुर वि0स0 का नाम भी शामिल है । अब कहा जा रहा है कि, दो दिनों के बाद बैकुण्ठपुर सहित शेष 07 वि0स0 सीट के लिये कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा की जावेगी । टिकिट दावेदारों को लेकर बैकुण्ठपुर वि0स0क्षेत्र में अफवाहों और चर्चाओं का दौर जारी है । आजकल हर चौक चौराहे होटल या पास ठेलों पर इसी बात को लेकर माथापच्ची हो रही है कि, कांग्रेस की टिकट कौन हासिल का पाएगा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस टिकिट के लिए आधा दर्जन दावेदारों के नाम विचार के लिए चल रहे थे उनमे वेदांती तिवारी आशा महेश साहु संगीता राजवाड़े कमला कांत साहु, अंबिका सिंहदेव अनिल जायसवाल आदि के नाम प्रमुखता से बताए जा रहे हैं । वेदांती और आशा दौड़ में आगे - कांग्रेस की टिकिट के लिये के लिए मचे घमासान में टिकिट वितरण कह अंतिम दौड़ में जिन दो दावेदारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है उनमें पीसीसी सदस्य व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी और

बैकुण्ठपुर ज0पं0 उपाध्यक्ष आशा महेश साहु है । जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार वेदांती तिवारी को भूपेश बघेल गुट का समर्थन है वहीं आशा महेश साहु को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहु का वरदहस्त प्राप्त है । वेदांती तिवारी वर्ष 2013 में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाए गए थे । जो काफी कम अन्तर लगभग 1200 वोट से भाजपा के भईयालाल राजवाडे से पराजित हुए थे । वर्ष 2018 के वि0स0 चुनाव में भी उनका नाम प्रस्तावित हुआ था लेकिन ऐन वक्त पर कुमार साहब की भतीजी अंबिका सिंहदेव को उम्मीदवार बना दिया गया था । पिछले चार पांच वर्षों में वेदांती तिवारी में काफी राजनैतिक संघर्ष किया था जिला कांग्रो के विरोध के बावजूद उन्होनें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और बाद में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे वहीं दूसरी और आशा महेश साहु का राजनैतिक कैरियर वर्ष 2019 में ही शुरू हुआ था जब वे जनपद सदस्य का चुनाव जीतकर ज0पं0 बैकुण्ठपुर की उपाध्यक्ष बनी थी । इस ज0पं0 में कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद ज0पं0 अध्यक्ष भाजपा समर्थित सौभाग्यवती बनी थी जो अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है ।

सर्वे को दी गई प्राथमिकता - कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बार-बार यह बात दोहरा रहे हैं कि, सर्वे के आधार पर टिकिट की प्राथमिकता तय की जा रही है । इस बात को लेकर कांग्रेस के वरि0 नेता टी0एस0 सिंहदेव ने भी अपने समर्थक दावेदारों से यह बात सार्वजनिक रूप से कही थी बताया जाता है कि, सर्वे में वर्तमान में वर्तमान विधायक अंबिका सिंहदेव काफी पीछे चल रही थी जिसकी वजह से संभवत: उनका नाम वरीयता में नहीं आ सका । हलांकि उन्हें वि0स0 अध्यक्ष डॉ0 महंत और टी0एस0 सिंहदेव का समर्थन प्राप्त है । वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेदांती तिवारी के पक्ष में सर्वे की गईतो काफी कांगेस के लिए उत्साहजनक रही । इसी कारण उनका नाम भी दावेदारों मं लगातार आगे चलता रहा ।

जिला विभाजन के बाद कांग्रेस का ग्राफ घटा- वर्ष 2022 में कोरिया जिले के विभाजन की घोषणा के साथ ही बैकुण्ठपुर वि0स0 क्षेत्र में कांग्रेस का ग्राफ गिरने के बाद वरि0 नागरिक और आमजन के अलावा कांग्रेस के ही

लोग लगातार कह रहे हैं कोरिया जिला विभाजन से कोरिया मात्र एक वि0स0 का जिला रह गया वहीं एम0सी0बी0 दो वि0स0 क्षेत्र के साथ ही जनसंख्या व क्षेत्रफल में काफी बड़ा जिला हो गया । यहां यह भी कहा जा रहा है कि, जोजिला कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में थे उन्हे भी आज तक कांग्रेस सरकार द्वार बैकुण्ठपुर में स्थापित नहीं किया गया है जिसमें लो0नि0वि0, जिला रोजगार अधिकारी, जिला उद्योग विभाग वाणिज्यिक कर कार्यालय आदि के नाम प्रमुखता से लिये जाते हैं । इन कारणों से संभवत कांग्रेस को कोरिया में बड़ा झटका मिला है इसका लाभ उठाने के लिए भाजपा अपने वरि0 नेता पिछड़ा वर्ग के श्री राजवाड़े को उतारा है।

कांग्रेस का पिछड़ा वर्गपर फोकस - इस बार कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग की राजनीति पर ज्यादा फोकस किया है इसी कारण संभवत: कांग्रेस की टिकिट के लिए पिछड़ा वर्गके दावेदारों संगीता राजवाड़े आशा महेश साहु कमला कांत साहु अनिल व अशोक जायसवाल का नाम पैनल में शामिल किया गया था । यह बताया जा रहा है कि, आशा महेश साहु का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है कि, वे पिछड़ा वर्गसाहु समाज से आती है जिनकी संख्या वि0स0 बैकुण्ठपुर मे 35000 से ज्यादा बताई जा रही है । टिकिट के लिए कांग्रेस से दावेदारों की दौड़ रायपुर से दिल्ली तक लगी है और दावेदार गुटीय राजनीति के

सहारे अपना-अपना दावा मजबूत कर रहे हैं । इस क्रम में बताया जाता है कि, बीते दिवस आशा महेश साहु कं समर्थन में अनेक कांग्रेसी छ0ग0 के उप मुख्यमंत्री टी0एस0 सिंहदेव से भी मुलाकात किए है ।

कांग्रेस के लोग प्रमुख रूप से टिकिट दावेदारी के लिये डा0 महंत, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहु, और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से अपना दावा पुख्ता करने की जुगत बना रहे हैं । कई कांग्रेस नेता दावेदारी मजबूत करने दिल्ली में राहुल गांधी और वेणुगोपाल से मुलाकात कर चुके हैं ।

कटघोरा सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग को टिकट नहीं

सामान्य वर्ग से प्रत्याशी बनाए जाने की उठती रही है मांग

कोरबा जिला का कटघोरा विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए है। मगर आपको यह जानकर हैरत होगी कि इस सीट पर कांग्रेस ने कभी भी सामान्य वर्ग को मौका नहीं दिया है। पहले कद्दावर आदिवासी नेता बोधराम कंवर और अब उनके पुत्र पुरुषोत्तम कंवर को यहां से कांग्रेस का टिकट मिला है। हालांकि इस बार सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठती रही है। राजनीति में वंशवाद की परंपरा को खत्म करने में कुछ खास सफलता नहीं मिलती दिख रही है। कोरबा जिले की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है जिसका उदाहरण कटघोरा विधानसभा में सामने आया है। यहां कांग्रेस के पूर्व

विधायक बोधराम कंवर ने अपनी सत्ता का उत्तराधिकारी पुत्र पुरुषोत्तम को बनाया है। पिछले चुनाव में एक बार मौका देने की बात हुई किंतु इस बार फिर से पुरुषोत्तम को ही टिकट दिया गया। इस बार प्रत्याशी घोषणा से पहले यह मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई कि कटघोरा विधानसभा जो कि सामान्य वर्ग के लिए है, यहां आदिवासी या दूसरे वर्ग का प्रत्याशी न उतर कर अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य वर्ग से दावेदार को मौका दिया जाना चाहिए। कटघोरा विधानसभा की विडम्बना है कि सामान्य सीट पर ओबीसी या सामान्य वर्ग के दावेदार को कांग्रेस से टिकट नहीं मिली बल्कि आदिवासी वर्ग से ही उम्मीदवार उतारे जाते रहे हैं। यहां सामान्य और पिछड़ा वर्ग के बहुसंख्यक करीब 70 फीसदी मतदाता कई वर्षों से कांग्रेस घोषित आदिवासी वर्ग के प्रत्याशी को चुनते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में कटघोरा ही एकमात्र ऐसी सीट है जहां सामान्य या ओबीसी वर्ग से प्रत्याशी कांग्रेस ने कभी नहीं उतरा। जबकि दूसरे विधानसभा का जिस वर्ग के लिए आरक्षण हुआ है, वहां उसी वर्ग के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। सामान्य सीट से ओबीसी या सामान्य को ही टिकट दी गई है किन्तु कटघोरा विधानसभा से पुरुषोत्तम कंवर को फिर से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पहले व बाद में भी विरोध के स्वर गूंजे हैं। इसके विपरीत भाजपा ने ओबीसी के लखनलाल देवांगन और अब प्रेमचंद पटेल को अवसर दिया है।

कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर-वेदराम के निर्णय पर टिकी सबकी नजरे

छग विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरंग विधानसभा क्षेत्र क्र 52 के लिए कांग्रेस के कद्दावर मंत्री एवं वर्तमान विधायक डॉ शिवकुमार डहरिया मैदान में है वही बीजेपी ने सतनामी समाज के गुरु बालदास साहेब के पुत्र गुरु खुशवंत को मैदान में उतारा दिया है।परंतु लोगो की नजरे अभी वेदराम मनहरे पर टिकी हुई है। राजनैतिक बाजार में उनके चुनाव लड़ने और नही लड़ने को लेकर कई कयास लगाये जा रहे है।

वेदराम लगातार अपने समर्थकों के साथ बैठके कर रहे है पर अभी तक उन्होंने अपना पत्ता नही खोला है। वेदराम के चुनावी मैदान में आने से किसे फायदा

होगा और किसे नुकसान इस पर भी चर्चाएं जोरो पर है। राजनितिक सूत्रों की माने तो वेदराम बीजेपी के अलावा कांग्रेस के वोटो पर सेंध मार सकते है इसीलिए दोनों पार्टियों की नजर उन पर लगी हुई है।

आपको बता दे की वेदराम मनहरे धार्मिक सामाजिक और राजनितिक आयोजनों ने लगातार सक्रीय रहे है और यही कारण है कि उनका आम मतदाताओं में अच्छी पकड़ बनी हुई है। और इसी पकड़ को भुनाने के लिए उनके समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए लगातार दबाव बना रहे है। वेदराम के चुनावी रण में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो जायेगा अन्यथा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी । कई क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने इस चुनाव में उतरेंगे।कांग्रेस और भाजपा अपना प्रचार अभियान शुरू कर आम मतदाताओं से लगातार जन संपर्क कर रहे है ऐसे में वेदराम मनहरे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मतदाताओं को कैसे साधेंगे यह देखने वाली बात होगी....।

मनेन्द्रगढ़ विधायक के 'हाथ' में 'आरी' देख कांग्रेस में मचा हड़कंप बगावती तेवरो से परेशान है राजनीतिक दल

कोरिया और एमसीबी जिले में भाजपा और कांग्रेस में अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा के बाद दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के सुर तेज होते जा रहे हैं । इससे दोनों दलों के नेता जहां परेशान है वहीं उनके कार्यकर्ताओं में भी असंमजस की स्थिति बढ़ती जा रही है । सबसे ज्यादा बगावत मनेन्द्रगढ़ वि.स. में देखी जा रही है । नामाकंन का दौर शुरू होने से बाद बागियों द्वारा भी नामाकंन पत्र लिया जाना वर्तमान अधिकृत प्रत्याशियों के लिये चिन्ता का सबब बनता जा रहा है।

विनय जायसवाल गोगंपा के साथ - मनेन्द्रगढ़ के वर्तमान विधायक डॉ. विनय जायसवाल की टिकिट कटने के बाद कांग्रेस के प्रति उनके तेवर तीखे हो गये हैं । उन्होनें सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि, वे गोंगपा से चुनाव लड़ेगे । उनके तेवर देख कांग्रेस संगठन में हडकंप मच गया है । अधिकृत प्रत्याशी रमेश सिंह औ विधायक डा. विनय जायसवाल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है । कई कांग्रेस नेताओं का कहना है कि, इस टकरार से कांग्रेस का ही नुकसान होना तय है । वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्य को कांग्रेस की उपलब्धि मानते हैं डॉ. जायसवाल की नहीं । डॉ. विनय समर्थकों को दावा है कि, मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने में मुख्यभूमिका डॉ. विनय ने ही निभाई है ।

ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष और पार्षद ने दिया इस्तीफा - कांग्रेस में इस्तीफा देने का भी दौर तेज हो गया है । वर्तमान विधायक डॉ. जायसवाल के समर्थन में ब्लाक कांग्रेस एवं खडगवां के अध्यक्ष मनोज साहु और चिरमिरी नगर निगम के पार्षद संदीप सोनवानी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है । मनोज साहु का कहना है कि, कांग्रेस हाईकमान ने गलत निर्णय है जिसका परिणाम वि.स. चुनाव में कांग्रेस को भुगतान पड़ेगा ।

भईया लाल ने खरीदी नामाकंन फार्म - बैकुण्ठपुर वि.स. के भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार गत दिवस कलेक्टर कार्यालय

पहुंच कर जिले का पहला नामाकंन फार्म लिया है । उनके साथ कृष्ण बिहारी जायसवाल और रविशंकर रजवाड़े उपस्थित थे । मिली जानकारी के अनुसार श्री राजवाड़े 29 अक्टुबर को अपना नामाकंन दाखिल करेंगें साथ ही उनके द्वारा भारी भीड़ इकट्ठा कर शक्ति प्रदर्शन की भी योजना बनाई जा रही है ।

शैलेष शिवहरे लड़ेगे निर्दलीय चुनाव - बैकुण्ठपुर वि.स. क्षेत्र से भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार टिकिट न मिलने से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है इसके लिये वे लगातार अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से राय मशविरा कर रहे हैं । उनकी गतिविधियों से भाजपा संगठन में हडकंप मच गया है । भाजपा के चुनाव प्रभारी नियुक्त भाजपा प्रदेश कमेटी द्वारा बैकुण्ठपुर वि.स. क्षेत्र और मनेन्द्रगढ़ वि.स.क्षेत्र के पार्टी के अधिकृत चुनाव संचालकों की नियुक्ति कर दी गई है । जिसके अनुसार बैकुण्ठपुर क्षे में लक्ष्मण राजवाड़े और मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के लिये द्वारिका जायसवाल को चुनाव संचालक नियुक्त किया गया है ।दोनों ही क्षेत्रों में अधिकृत प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया गया है ।

मनराज ने भी खरीदा नामाकंन फार्म- मनेन्द्रगढ वि.स.क्षेत्र में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार श्यामबिहारी जायसवाल के लिए चिरमिरी के मनराज मौर्य ने चुनौती पेश कर दी है । उन्होनें भाजपा हाईकमान के निर्णय को गलत और पक्षपात पूर्ण बताते हुए कहा है कि, टिकिट वितरण में मनेन्द्रगढ़ वि.स. क्षेत्र के सबसे बड़े चिरमिरी की उपेक्षा की गई है । जिससे ज्यादातर भाजपा वर्ग में असंतोष व्याप्त हो गया है । मनराजमौर्य प्रदेश भाजपा पि. गर्व प्रकोष्ठ के कार्यसमिति सदस्य है । उन्होने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है।

केन्द्रीय मंत्री ने मैनेज किए मैनेज - भरतपुर सोनहत क्षेत्र में स्थिति भाजपा और कांग्रेस के संतोषजनक है भाजपा में बाहर उम्मीदवार को लेकर जो असंतोष का तूफान खड़ा हुआ था वह थमता नजर आ रहा है दो अन्य प्रबल दोवेदारों रविशंकर सिंह एवं दृग्पाल सिंह को रेणुका सिंह ने अपने पक्ष में कर लिया है। जिससे उनकी स्थिति में सुधाार आ गया है। भाजपा के पदाधिकारी पूरी सक्रियता से चुनाव में लग गए प्रतीत हो रहे हैं।

कांग्रेस में छाई है मायूसी - बैकुण्ठपुर वि.स. में कांग्रेस द्वारा अभी तक अपने अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है । जिससे कांग्रेसियों में मायूसी बनी हुई है टिकिट दावेदारों के समर्थकों द्वारा अपने-अपने दावेदारों को लेकर मजबूत स्थिति बताई जा रही है जिमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ज.पं. उपाध्यक्ष आशा साहु का नाम बना हुआ है ।

कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरों एवं भाजपा के प्रत्याशी रेणुका के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौरा चला

विधानसभा नंबर वन भरतपुर जिला एम,सी,बी में रेणुका सिंह एवं गुलाब कमरो के बीच क्षेत्र के विकास को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए ठनी । जहां एक और गुलाब कमरो ने बीजेपी पर झूठे आरोप ,लगाया है दूसरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भरतपुर सोनहत से बीजेपी की प्रत्याशी रेणुका . रेणुका सिंह ने कहा भरतपुर सोनहत ने विकास महज कागजों तक और भूमि पूजन सीमित रहे।

चुनावी भाषण में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं. इस बीच भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी एक दूसरे पर विकास कार्यों को लेकर आरोप लगा रहे हैं. जहां एक ओर भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो ने बीजेपी पर 15 साल तक जनता को ठगने का आरोप लगाया है प्रत्याशी गुलाब कमरो ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है. कांग्रेस काम करती है तो बीजेपी बयान,बाजी करती है. कि 15 लाख खाते में आएगा. 2 करोड़ को नौकरी मिलेगा.2018 में कांग्रेस ने 36 घोषणाएं की थी. 51 योजना संचालित है. इसलिए हम लोग विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं. आने वाले दिन में हम लगातार विकास करेंगे. नया जिला है, नए जिले में तेजी से विकास होगा. यहां हम मेडिकल कॉलेज बना दिए. रमन सिंह ने यही जिला जब कोरिया था, जिसको गोद में लिए थे. 15 साल ठगने का काम किया है.रेणुका सिंह के बयान पर सियासी भूचाल, कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यजनक भरतपुर सोनहत में कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग हुई तेज, विवादित बयान मामले में रेणुका सिंह को नोटिस पूर्व विधायक चम्पादेवी पावले ने बताया बाहरी, नहीं है भरतपुर सोनहत,विधानसभा उनका मायका है,बीजेपी ने किया पलटवार भाजपा के प्रत्याशी रेणुका सिंह ने गुलाब कमरो के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि, वह अपने क्षेत्र में कितना ध्यान दिए हैं जनता का कितना ख्याल रखा है क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कितना काम किया है यहां केवल कागजों पर विकास हुआ है. सांसद और भारत सरकार में मंत्री होने के नाते मुझे दिल्ली सहित अन्य राज्यों में समय देना पड़ता है. मैंने पूरे देश का दौरा किया है. जनजातियों के बीच मैं गई हूं. अपने मंत्रालय के माध्यम से देश के 75 जनजाति समुदाय, जैसे बैगा जनजाति, सरगुजा क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा हैं।

शिवरतन को व्यक्तित्व का सहारा तो कांग्रेस प्रत्याशी इंद्र साव पार्टी के सहारे

विधानसभा चुनाव को लेकर अब धीरे-धीरे चुनावी सरगर्मी तेज होते जा रही है। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सातवीं बार शिवरतन शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है 1993 से शिवरतन शर्मा भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते आ रहे हैं वहीं इस बार कांग्रेस ने बिल्कुल नए चेहरे इंद्र साव के नाम पर दाव खेला है।

दोनों प्रत्याशी और दोनों दलों के लोग अब चुनावी जनसंपर्क में तेजी के साथ भिड़ गए हैं इस बार चुनाव में भाजपा के शिवरतन शर्मा को जहां अपने व्यक्तित्व का

सहारा है तो कांग्रेस प्रत्याशी इंद्र साव को पार्टी का सहारा है। मैदान में दोनों डटे हुए हैं कांग्रेस के अंदर थोड़ा बहुत असंतोष का माहौल जरूर दिखाई दे रहा है पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर का कहना है कि सब मामले को बैठकर सुलझा लिया जाएगा और भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। फिलहाल बिना मुद्दे के चुनाव प्रचार चल रहा है सुबह से लेकर रात तक के चुनाव प्रचार में दोनों प्रत्याशी लगे हुए हैं अभी पोस्टर बैनर वॉर शुरू नहीं हो पाया है शिवरतन शर्मा जहां सुबह के समय भाटापारा शहर में जनसंपर्क करते हैं वहीं दोपहर बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं कुछ इसी तरह का कार्य कांग्रेस

प्रत्याशी इंद्रसाव के द्वारा भी किया जा रहा है वह भी वह भी अपना प्रोग्राम बनाकर जनसंपर्क करने के कार्य में जुटे हुए हैं। परंतु इतना अवश्य सत्य है कि शिवरतन शर्मा भारतीय जनता पार्टी में एक का दवा नेता के रूप में जाने जाते हैं इसलिए उन्हें इस चुनाव में उन्हें अपने व्यक्तित्व का ही सहारा है जबकि इंद्र साव भी चार बार के पार्षद रह चुके हैं इसके साथ-साथ उन्हें पार्टी का सहारा है। दोनों कब नामांकन दाखिल करेंगे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है परंतु प्रचार शुरू हो चुका है और लोग कयास लगाना भी शुरू कर चुके हैं लेकिन इतनी जल्दी कयास नहीं लगाया जा सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी सरकार में हो रहा पूर्वोत्तर का विकास : राजनाथ सिंह

आईजोल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को मिजोरम विधानसभा चुनाव को लेकर वह प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 20 सालों से भी अधिक समय से मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करता रहा हूं। कनेक्टिविटी की समस्या को बड़े ही नजदीक से मैनें देखा है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि नार्थ-ईस्ट के राज्यों की सभी राजधानियों तक पहुंचने के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं था। आज हालात एकदम बदल गए हैं। आज हर नार्थ-ईस्ट राज्य में देश की राजधानी दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी है, क्योंकि हर राज्य को आज एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि जब दिल्ली में कांग्रेस का शासन था तो मिजोरम और उत्तर पूर्वी राज्य न केवल दूर थे बल्कि हमारे दिलों से भी दूर थे। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्वोत्तर का तेजी से विकास हुआ है।

मध्यप्रदेश में खेल बिगाड़ेंगे कांग्रेस और भाजपा के बागी

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर है। हालांकि, दोनों बड़ी पार्टियों के लिए बगावत सबसे ज्यादा सिरदर्द बना हुआ है। प्रदेश सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाह इस बार निवाड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां बड़ी हैं। टिकट नहीं मिलने पर आमिर अकिल, जीतेंद्र डागा, कमलेश्वर देवलिया, केके श्रीवास्तव, कमलेश अग्रवाल, शैलेन्द्र चौधरी, जयकांत सिंह, राजेंद्र सिंह सोलंकी, कौशल्या गोटिया समेत कई नेता नाराज हैं। अपने इलाके में दबदबा रखने वाले इन नेताओं की एंट्री से आलाकमान चिंतित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश संगठन महासचिव हितानंद शर्मा बीजेपी में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं से बात कर रहे हैं।

एथिक्स कमेटी पेश होने के लिए बना रही है दबाव : महुआ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले में गुरुवार को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी। इससे पहले उन्होंने कमेटी से सामने एक खास मांग भी रख दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जिरह की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जरूरत है कि हीरानंदानी से भी पूछताछ की जानी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने एथिक्ट कमेटी को एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने यह भी दावा किया कि संसदीय समितियों को आपराधिक मामलों में जांच का कोई अधिकार नहीं है। महुआ मोइत्रा ने इस पत्र में आरोप लगाया कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मामले में सुनवाई की तारीख बढ़ाने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और उन पर पेश होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने हीरानंदानी से भी पूछताछ करने की मांग रखी है।

राघव चड्ढा ने कहा केजरीवाल आज हो सकते हैं गिरफ्तार!

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की परेशानी आने वाले समय में बढ़ सकती है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज गुरुवार को ईडी उनसे पूछताछ करेगा। इधर, दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल से होने वाली पूछताछ को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी नेता और सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी को चुनावों में हार का डर सता रहा है इसलिए वो आप के बड़े नेताओं को जेल में डाल रही है। ताकी वो चुनाव ही न लड़ सके और बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो सके। राघव चड्ढा ने कहा है ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी की एजेंसियां केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी के निशाने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी है।

उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराएंगे : सपा

लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कमर कसनी शुरू कर दी है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से मात खाने वाली सपा ने ऐलान किया है कि वो आगामी आम चुनाव में भाजपा को एक भी लोकसभा सीट नहीं पाने देगी। सूत्रों के मुताबिक सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा का लक्ष्य तय हो गया है और हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता हराएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्याक) का नारा दिया है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे।

भारत-बांग्लादेश रिश्तों की एक और नई इबारत

मोदी और शेख हसीना ने 3 बड़ी परियोजनाओं का किया उद्घाटन

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीन विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर पीएम शेख हसीना ने कहा,...मैं हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूं।

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह खुशी की बात है कि एक बार फिर हम भारत-बांग्लादेश सहयोग की सफलता का जश्न मनाने के लिए जुड़े हैं। हमारे रिश्ते लगातार नई ऊंचाईयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जो काम किया है, वह इससे पहले के दशकों में भी नहीं हुआ था। मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दोनों देशों के बीच दशकों से लंबित, जमीन सीमा समझौता किया गया और समुद्री सीमा संबंधी मामलों को भी सुलझाया गया।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत-बांग्लादेश ने अवसंरचना और संपर्क के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले नौ वर्षों में तीन नयी बस सेवाएं और तीन नयी रेल सेवाएं शुरू किए जाने का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि साल 2020 से तो भारत-बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेन भी चल रही हैं। उन्होंने कहा, ''पिछले नौ वर्षों में समुद्री मार्ग को सवारी और माल के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए निर्यात का रास्ता खुल गया है।''

मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच विश्व की सबसे बड़ी क्रूज सेवा 'गंगा विलास' के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है जबकि चटगांव और मोंगला बंदरगाह के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़े जाने का लाभ भी दोनों देशों को हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क पहल ने कोरोना महामारी के दौरान जीवनरेखा

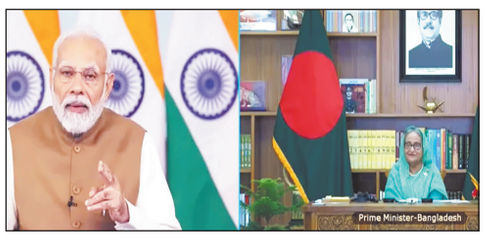

का काम किया और तभी 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस' के जरिए 4,000 टन से ज्यादा ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई गई।

क्या हैं भारत-बांग्लादेश के बीच की तीन विकास परियोजनाएं?

ये तीनों परियोजनाएं भारत की सहायता से क्रियान्वित की गई हैं। इनमें अखौरा-अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक, खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट-तीन, परियोजना शामिल हैं। अखौरा-अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक परियोजना को भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के तहत क्रियान्वित किया गया है। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश में 6.78 किमी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किमी के साथ रेल लिंक की लंबाई 12.24 किमी है।

खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना को भारत सरकार की रियायती कर्ज सुविधा के तहत 38.83 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना लागत के साथ तैयार किया गया है। इस परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच करीब 65 किमी ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला ब्रॉड-गेज रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। 15 किमी लंबा अगरतला-अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क (भारत में 5 किमी और बांग्लादेश में 10 किमी) सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देगा और ढाका के रास्ते अगरतला से कोलकाता आने-जाने में लगने वाला समय भी घटाएगा। फिलहाल, ट्रेन को अगरतला से कोलकाता पहुंचने में 31 घंटे लगते हैं, जो इस परियोजना के शुरू होने के बाद 21 घंटे रह जाएंगे।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ग्वालियर-कोझिकोड शहर शामिल

नई दिल्ली। कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा, यह सांस्कृतिक आख्यानों को पोषित करने के सामूहिक प्रयास को दर्शाता है। कोझिकोड की समृद्ध साहित्यिक विरासत और ग्वालियर की सुरीली विरासत के यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने से भारत की सांस्कृतिक जीवंतता वैश्विक मंच पर चमक रही है। पीएम मोदी ने कहा, इस उपलब्धि पर कोझिकोड और ग्वालियर के लोगों को शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्र हमारी विविध सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में दो और भारतीय शहरों को शामिल किया जाना देश के लिए गर्व का क्षण है। भारत से ग्वालियर और कोझिकोड उन 55 नए शहरों में शामिल हैं, जो मंगलवार को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत के शहर और साहित्य के शहर के रूप में शामिल हुए। विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को महानिदेशक ऑड्रे अजोले द्वारा 55 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) में शामिल हो गए। विश्व निकाय के मुताबिक, नए शहरों को उनकी विकास रणनीतियों के हिस्से के रूप में संस्कृति और रचनात्मकता का उपयोग करने और मानव-केंद्रित शहरी नियोजन में नवीन प्रथाओं को प्रदर्शित करने की उनकी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए स्वीकार किया गया।

राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

कांग्रेस तालिबानी सोच की सरकार पवन खेड़ा ने किया पलटवार

जयपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजराइल-गाजा युद्ध और राजस्थान में कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई के बीच समानताएं बताईं। राजस्थान के अलवर में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या आप देख रहे हैं, गाजा में तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचला जा रहा है? लक्ष्य पर निशाना लगाना और सटीकता से उसे कुचलना। उन्होंने आगे कहा कि तालिबान का समाधान बजरंग बली की गदा है। राजस्थान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अराजकता, गुंडागर्दी और आतंकवाद समाज के लिए अभिशाप है। जब इनमें राजनीति शामिल हो जाती है तो इसका असर सभ्य समाज पर पड़ता है।

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार पटेल ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, लेकिन कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू ने यहां भी समस्याएं पैदा कीं, जिससे आतंकवाद फैल गया। इसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को समस्या मुक्त बनाया। वहां से आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाए गए। उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामलों पर भी राजस्थान सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि याद रखें अगर कांग्रेस सफल रही तो तालिबानी मानसिकता के कारण बहनों और बेटियों का शोषण किया जाएगा।

योगी ने कहा कि देश जिन समस्याओं का समाधान एक एक कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज कर रहा है वे सभी समस्याएं कांग्रेस की देन हैं। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान करने का नाम ही 'डबल इंजन' की सरकार है। उन्होंने कहा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की 'डबल इंजन' की सरकार है वहां सुरक्षा, समृद्धि और विकास है तथा वहां बिना भेदभाव के शासन की

योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। योगी पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि मैं किसी को भी अपने राज्य का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश में कल गुंडों ने पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी। कृपया अपना राज्य संभालें...वे अपना राज्य नहीं संभाल सकते और यहां आ जाते हैं।

राजस्थान में टिकट आवंटन पर कांग्रेस में विरोध

राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अजमेर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने अपनी 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 156 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इससे पहले भी पार्टी के भीतर नाराजगी की खबर आई थी। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि हर कोई संतुष्ट नहीं होगा और लोकतंत्र में मुख्यमंत्री भी अन्य पार्टी के नेताओं से परामर्श किए बिना सभी निर्णय नहीं ले सकते। अशोक गहलोत ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। भले ही मैं सीएम हूं, लेकिन सभी फैसले वैसे नहीं ले सकते, जैसे मैं चाहता हूं। यही लोकतंत्र है।

खेल
प्रमुख समाचार

मुंबई में भारत और श्रीलंका का मुकाबला आज

मुंबई। आज टीम इंडिया के सामने श्रीलंका की टीम होगी। भारत अंक तालिका में 6 मैच में 12 अंक लेकर सबसे आगे है। श्रीलंका की टीम के पास मात्र 4 अंक और 7वें स्थान पर है। मैच दोपहर दो बजे से शुरू होगा। भारत ने हर विभाग में एक चैम्पियन की तरह प्रदर्शन किया है। आत्मविश्वास के उफान का कारण यह भी है कि कठिन हालात से भारत ने वापसी करके जीत दर्ज की है मसलन चेन्नई में आस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच रन पर तीन विकेट गंवाना हो या इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में नौ विकेट पर 229 रन के साधारण स्कोर के बावजूद जीत दर्ज करना हो।

श्रीलंका के लिये सदीरा समरविक्रमा ने छह मैचों में सर्वाधिक 331 रन बनाये हैं जिसमें एक शतक शामिल है। पाथुम निसांका ने भी इस साल एक हजार से अधिक वनडे रन बनाये हैं। विश्व कप में उन्होंने लगातार चार अर्धशतक जड़े हैं। कप्तान कुसल मेंडिस और एंजेलो मैथ्यूज के रूप में श्रीलंका के पास मैच विनर खिलाड़ी हैं। श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन अनुभव के अभाव में भारतीय बल्लेबाज उनके लिये बड़ी चुनौती साबित होंगे।

भारत-रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन इशान किशन ,सूर्यकुमार यादव।

श्रीलंका- कुसल मेंडिस (कप्तान), कुसल परेरा, पथुम निसांका, दुशमंत चमीरा, दिमुथ करुणारत्ने, सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, महेश तीक्षणा, डुनिथ वेलालेज, कासुन राजिथा, एंजेलो मैथ्यूज, दिलशान मदुशंका, दुशान हेमंथा, चमिका करुणारत्ने।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 284 अंक टूटा निफ्टी 19,000 के नीचे

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले-जूले रुझानों के बीच मेटल और कुछ चुनिंदा ब्लू चिप शेयरों में लगातार बिकवाली के दबाव के कारण हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। आज दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 284 अंक कमजोर हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 90 अंक की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 283.60 अंक यानी 0.44त्न फीसदी की गिरावट के साथ 63,591 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 63,896 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 63,550 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 90.45 अंक यानी 0.47 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 18,989 अंक पर बंद हुआ।

कमर्शियल सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली। देश भर में तेल मार्केटिंग कंपनी ने बुधवार को देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। सिलेंडर के दामों में हुई यह बढ़त 101.5 रुपये की है। इस बात का ऐलान तेल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) ने बुधवार को कीमतों में संशोधन कर किया है। अब 1 नवंबर से दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत अब 1731.5 रुपये से बढ़कर 1,833 रुपये हो जाएगी। चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर के दाम 1,999 रुपए, मुंबई में 1,785 रुपए और कोलकाता में 1,943 रुपए कीमत पर मिलेगा। यह दूसरी बार है जब देश भर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। अक्टूबर में यह बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में 209 रुपए प्रति सिलेंडर की हुई थी। वहीं, अगस्त और सितंबर में 250 रुपए की दाम में कमी की गई थी।

टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री में 5.89 प्रतिशत की तेजी

नईदिल्ली। देश की प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स की कुल बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 5.89 प्रतिशत बढ़कर 82,954 इकाई रही। कंपनी की कुल घरेलू बिक्री 80,825 इकाई रही, जो अक्टूबर 2022 में 76,537 इकाई थी। टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि अक्टूबर में यात्री वाहन (इलेक्ट्रिक वाहन समेत) खंड में घरेलू बिक्री सालाना आधार पर सात प्रतिशत बढ़कर 48,337 इकाई रही। अक्टूबर 2022 में यह 45,217 इकाई थी। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कुल बिक्री (अंतरराष्ट्रीय बाजार समेत) अक्टूबर में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर 5,465 इकाई रही, जो पिछले साल अक्टूबर में 4,277 इकाई रही। इसकी कुल वाणिज्यिक वाहन बिक्री पिछले महीने चार प्रतिशत बढ़कर 34,317 इकाई हो गई, जो अक्टूबर 2022 में 32,912 इकाई थी।

टोयोटा की गाड़ियों की खरीद, 66 फीसदी बढ़ी सेल

नईदिल्ली। जापान की वाहन कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की गाड़ियों में लोगों की रुचि बढ़ रही है। इस बात का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि साल 2023 के अक्टूबर महीने में सालाना आधार पर बिक्री 66 प्रतिशत बढ़कर 21,879 इकाई हो गई। वहीं बीते साल इसी दौरान यानी अक्टूबर 2022 में कंपनी ने डीलरों को 13,143 वाहन भेजे थे। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, 'अक्टूबर में घरेलू बाजार में उसकी बिक्री 20,542 इकाई रही। वहीं 1,337 इकाइयों का निर्यात किया गया।' टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष-बिक्री और रणनीतिक विपणन अतुल सूद ने बताया कि सेल में ये बढ़त भारत मे चल रहे त्योहारी सीजन के कारण देखी जा रही है। आगे उन्होंने कहा, '' हर खंड में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसमें टोयोटा मौजूद है। '

मजबूत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल हैं भारत के लिए हालात

अजय बग्गा

भारत कई क्षेत्रों में जबर्दस्त प्रगति का साक्षी रहा है, जिसमें डिजिटलीकरण, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना, विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने की खातिर बेहतर नीतिगत माहौल और बुनियादी ढांचे पर खर्च में भारी वृद्धि शामिल है। नीतियों की निरंतरता के कारण भारत के सकारात्मक विकास के लिए आधार तैयार किए गए हैं।

वित्त वर्ष-24 की पहली तिमाही में 7.8 फीसदी की वृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस वृद्धि को मजबूत खपत, बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट क्षेत्रों में चल रहे निवेश, सेवा निर्यात में निरंतर वृद्धि, एक संपन्न सेवा क्षेत्र, सकारात्मक उपभोक्ता और व्यावसायिक विकास का समर्थन हासिल है। रिजर्व बैंक के ताजा अनुमानों में वित्त वर्ष-2024 में भारत के लिए 6.5 फीसदी और वित्त वर्ष 2025 में 6.2 फीसदी की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कई नीतिगत सुधार और समर्थन, सरकार द्वारा विशाल पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किए जाने, मजबूत कॉरपोरेट एवं बैंक बैलेंस-शीट ने (जिनमें एनपीए पर काबू पा लिया गया है) आने वाले लंबे समय के लिए निरंतर आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

वर्ष 2014 में वैश्विक जीडीपी के मामले में दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा भारत अब पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी सुधार हुआ है और वर्ष 2014 के 147वें पायदान से ऊपर उठकर अब यह 127वें पायदान पर आ गया है। इस दौरान जीएसटी, आईबीसी, जनधन, आधार, यूपीआई और

पीएलआई योजनाएं जैसे ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। मुद्रास्फीति पर भी उल्लेखनीय नियंत्रण हुआ है। ऐसा एमएसपी में कम वृद्धि, सौभाग्य से कच्चे तेल/वस्तु की कीमतों में कमी और कोविड के दौरान विवेकपूर्ण उपायों से हुआ है। इसके अलावा, व्यावसायिक सुगमता सूचकांक में भारी उछाल के साथ कारोबारी धारणा में सुधार हुआ है। और अब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

बुनियादी ढांचों के विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अपना निवेश बढ़ाया है। पिछले नौ वर्षों में राजमार्गों में लगभग 60 फीसदी की वृद्धि हुई है और रेलवे के बुनियादी ढांचे में निवेश चार गुना से अधिक बढ़ गया है। बंदरगाहों की क्षमता में 83 फीसदी की वृद्धि हुई है। मेट्रो लाइन की लंबाई साढ़े तीन गुना बढ़ी है, जिससे और अधिक शहर मेट्रो रेल लाइन से जुड़ गए हैं। उड़ान योजना के तहत 73 नए हवाई अड्डों के संचालन का काम हुआ है। वित्तीय समावेशन और डिजिटाइजेशन के मोर्चे पर भी भारी सफलता मिली है। वर्ष 2014 के बाद से खोले गए 50 करोड़ जन-धन खातों की बदौलत वर्ष 2023 में 80 फीसदी से ज्यादा लोगों के बैंक खाते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वर्ष 2014 में 7,400 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर सात लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार ने सब्सिडी देने के लिए जन धन-आधार-मोबाइल-पैन का प्रभावी ढंग से उपयोग करके विलंब और बिचौलियों को खत्म कर दिया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने भी जबर्दस्त प्रगति की है। ऑटोमोबाइल की बिक्री में वृद्धि, बिजली की बढ़ती मांग, ई-वे बिल की मात्रा, पैसेंजर ट्रैफिक में वृद्धि, घरेलू क्षेत्र में बैंक ऋण के प्रवाह में उच्च वृद्धि और ग्रामीण मांग वृद्धि में सुधार बढ़ते उपभोग का संकेत देते हैं। बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट क्षेत्र फल-फूल रहे हैं, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि, सीमेंट, स्टील की खपत और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च में परिलक्षित होता है। कुल मिलाकर, बैंकों और कॉरपोरेट्स की स्वस्थ बैलेंस शीट, आपूर्ति श्रृंखला सामान्यीकरण, व्यावसायिक आशावाद, मजबूत उपभोक्ता भावना और मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय भारत में मजबूत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल हैं।

भाजपा सरकार धर्मांतरण रोकेगी : सतपाल

■ ट्रेन के आगे भी भाजपा का इंजन और ट्रेन के पीछे भी भाजपा का इंजन होगा तो ट्रेन अपनी मंजिल को पहुंचेगी:सतपाल महाराज

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मगुरु और उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में घोटाले-ही-घोटाले किए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए दिए लेकिन कांग्रेस ने जनता तक पहुँचने नहीं दिए। श्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य बनने के बाद 3 साल कांग्रेस की सरकार का कुशासन रहा, और फिर 15 साल भाजपा को अवसर मिला तो विकास के कई कार्य भाजपा की सरकार ने किया और फिर से कांग्रेस को 5 साल जब अवसर मिला तो उसने छत्तीसगढ़ का पूरा खजाना लूटकर गांधी परिवार भेजने का काम किया। यहां के लोगों का हक मारने का काम किया।

भाजपा नेता और उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने छत्तीसगढ़ में भाजपा को विजयी बनाकर यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार न होने से छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान हुआ है केंद्र का दिया पैसा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़वासियों तक नही पहुंचने दिया। श्री सतपाल महाराज ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति लगभग 10 हजार साल पुरानी है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के बड़े आत्मीय संबंधों की चर्चा करते हुए श्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का मंदिर और छत्तीसगढ़ के शिवरीनीरायण का मंदिर भगवान विष्णु की पूजास्थली है। भविष्य में हम छत्तीसगढ़. उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश को रामायण और महाभारत सर्किट के रूप में आगे बढ़ाएंगे। इस पर उत्तराखंड का पर्यटन मंत्रालय काम कर रहा है। श्री सतपाल महाराज ने कहा कि

आज के दिन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीन राज्य बने थे। हमारी कामना है कि छत्तीसगढ़ दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। परम श्रद्धेय अटलजी ने यह जानते हुए भी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, छत्तीसगढ़ राज्य को साकार स्वरूप दिया और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। इसलिए वे विशेष रूप से यहाँ यह कहने आए हैं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाइए। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जब रेल चढ़ती है तो एक इंजन आगे और एक इंजन पीछे लगता है, तब रेल अपने गंतव्य तक पहुँचती है। इसी प्रकार केंद्र में भाजपा सरकार है, यहाँ पर भी भाजपा सरकार बनेगी, तो विकास के लिए जो भी फण्डिंग की आवश्यकता होगी, वह पूरी होगी और छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। भाजपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकार के 15 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री सतपाल महाराज ने कहा कि छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही इसे सँवारेगी।

भाजपा नेता और उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विकास के कामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रणी रहे हैं। अभी जी-20 सम्मेलन के सफल आयोजन से भारत की जय-जयकार पूरे विश्व में होती रही।

रूस यूक्रेन के युद्ध के समय जिनके हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज था और भारत माँ की जय बोल रहे थे, वे सब सुरक्षित लौटकर आए। इसी तरह इजराइल से भी भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। श्री सतपाल महाराज ने कहा कि श्री मोदी ने अपनी दृढ़ नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है और बिना किसी द्वंद्व के पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। भारत ने विश्व के अनेक देशों को अनाज निर्यात किया, कोरोना की वैक्सीन दुनिया के प्रायः सभी देशों को भेजी गई। कोरोना काल में जब विश्व भारतीय अर्थ व्यवस्था के नष्ट हो जाने की आशंका व्यक्त कर रहा था, तब प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के मूलमंत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत बनाकर आज विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है।

भाजपा नेता व उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतारण होना दुःखद है। सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन, कांग्रेस सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की। गरीबों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। यदि यह दुष्चक्र चलता रहा तो वंचित और आदिवासी समुदाय अपने आस्था केंद्रों और संस्कृति की रक्षा कैसे कर पाएगा? भाजपा धर्मांतरण पर रोक लगाएगी।

मतदान वाले दिन जनता कांग्रेस के झूठ का हिसाब करेगी: मूणत

रायपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राजेश मूणत बुधवार को अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान खमतराई स्थित श्री श्री सोलापुरी माता के दर्शन करके छत्तीसगढ़ की खुशहाली और उन्नति के लिए प्रार्थना की।

माता के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि मैं हर दिन अपने जनसम्पर्क अभियान की शुरुआत देवालयों में दर्शन लाभ लेकर करता हूं, किंतु आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है,इसलिए भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में माता शोलापुरी की वंदना करके दिन की शुरुआत की है। मां से प्रार्थना है कि वह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद देकर रायपुर पश्चिम समेत संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हमे जनदेवा करने का अवसर प्रदान करे।

बहरहाल राजेश मूणत भाजपा के जनसंपर्क अभियान के दौरान लगातार बैठको , डोर टू डोर जनसंपर्क और रैलियों सभाओं में शामिल हो रहे हैं। श्री मूणत ने बताया कि जब मैं लोगों के घर जाता हूं, तो ऐसा एहसास ही नही होता है कि मैं चुनाव प्रचार में निकला हूं ,अपितु मुझे तो अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ वक्त गुजराने का एहसास होता है। भले ही बीते 5 साल वक्त मुश्किल रहा, लेकिन रायपुर पश्चिम क्षेत्र की जनता ने मुझे सदैव उतना ही प्यार दिया है।मुझे जनता से एक नेता से अधिक मुझे परिवार के सदस्य की तरह लोगो का स्नेह प्राप्त हो रहा है। मूणत ने आगे कहा कि जनता से मिल रहे अभूतपूर्व प्रेम से अभिभूत हूं। यह प्रेम मुझे जनसंघर्ष करने की प्रेरणा देता है,इसलिए जनता की उम्मीदों में बंधकर ,मैं तमाम थकान के बाबजूद पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव जीतने के लिए अपने संकल्प को रोजाना दोहरा पाता हूं। जनसम्पर्क अभियान के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि आज हमने लगभग 2200 घरों तक अपनी पहुंच दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन विशेष था,इसलिये हमने सुबह सोलापुरी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जनसंपर्क की शुरुवात की।

सरोज ने निकाली कांग्रेस की घोषणाओं की हवा, भूपेश बघेल के झूठ का पर्दाफाश

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया और इसे भाजपा ने ही सवारा है और पांच साल में

कांग्रेस की सरकार ने जो विकास अवरूध्द किया है उसे हमारी सरकार फिर से नये आयाम देगी। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस बात को स्वीकार किया कि केंद्र सरकार धान खरीदी का 2200 रुपए देती है और केवल 600 रुपए राज्य की सरकार देती है। जयराम रमेश जी को साधुवाद है। कम से कम सच बोलने की उन्होंने हिम्मत तो दिखाई। लेकिन इस विषय पर मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछना चाहते हैं वे जो बार-बार इस बात को बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि केंद्र की सरकार कोई सहयोग नहीं करती एक तरफ उनके उपमुख्यमंत्री केंद्र की सरकार को सराहते है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी बार-बार आरोप लगाते हैं। उपमुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं। दोनों में कोई ना कोई जरूर झूठ बोलता है तो यह तय होना चाहिए कि झूठ कौन बोलता है। *5 साल पहले बोला था पूरा किसानी का कर्जा माफ करेंगे प्राइवेट बैंकों का भी करेंगे नही हुआ* *अब फिर घोषणा* कांग्रेस की घोषणाओं संबंधी विज्ञापन पर कटाक्ष करते हुए भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे। यह घोषणा उनके पूर्व के जन घोषणा पत्र में भी थी। जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा है वह बातें पूरी नहीं हुई यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी फिर से कर्ज माफी की बात करते हैं। पिछले बार जो कर्ज माफी की बात उन्होंने कही थी उसमें दीर्घकालिक, अल्पकालिक, ट्रैक्टर से संबंधित लोन और तो और प्राइवेट लोन की बात भी हुई थी जिसको मुख्यमंत्री ने माफ नहीं किया। 5 साल बीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जी एक जुमला फेकते हैं। *शिक्षा की पिछली घोषणा हवा में उड़ गई* *बच्चो को नही मिली सायकल* उन्होंने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। पहले 12वीं तक मुफ्त शिक्षा की बात कही थी। पांच साल बाद फिर केजी पर आ गए साफ है कि पिछली घोषणा हवा में उड़ गई।

मुख्यमंत्री बघेल के झूठ की पोल उनके ही नेता खोल रहे: डॉ. रमन

■ धान की एमएसपी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह दिया धन्यवाद

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के झूठ की पोल उनके ही नेता खोल रहे हैं।

दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जयराम रमेश ने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए एमएसपी के बारे में बताया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 80 प्रतिशत से ज्यादा पैसा किसानों को केंद्र सरकार देती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की एमएसपी अगर 2200 रु है तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार शेष राशि मात्र दे रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा यह कहते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान खरीदी का पूरा पैसा राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं होता। ऐसे में जयराम रमेश के इस बयान ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार की पोल खोल दी है इसे लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार के कार्यों का श्रेय लेकर किसानों से झूठ बोल रही है और उन्हें छलने का प्रयास कर रही है लेकिन चुनाव के ठीक पहले किसानों के सामने कांग्रेस के मुंह से सच निकल ही गया , मुझे लगता है कि अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रह गया, सब समझ गए कि प्रदेश में पिछले 5 साल से एक लबरा कितनी लबारी मार रहा है और झूठ बोलकर छत्तीसगढ़वासियों को धोखा दे रहा है।

विकास के लिए बीजेपी को जिताना जरूरी: पुरंदर

रायपुर। राजधानी रायपुर में चुनाव का माहौल देखते ही बन रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और मैदान में खड़े निर्दलीय उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा की चुनावी तैयारी चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है।

उत्तर विधानसभा क्षेत्र की हर गली और मुहल्ले तक श्री मिश्रा पहुंच रहे हैं। लोगों से रु-ब-रु मुलाकात कर रहे हैं। दौरा और जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत बुधवार शाम को सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने भाजपा मंडल शंकर नगर इलाके के दुर्गा नगर, वार्ड-34 और लाल बहादुर वार्ड का सघन दौरा किया।

बृजमोहन ने किया भाजपा कार्यालय का शुभारंभ

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को रायपुर दक्षिण के लाखे नगर मंडल के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। यह कार्यालय केलाबाड़ी, आदर्श नगर, कुशालपुर में खोला गया है। इस कार्यालय के खुलने से लाखे नगर मंडल में चुनाव अभियान में और तेजी आएगी।

कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल ने मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। कार्यकर्ताओं से गरीबों को न्याय दिलाने, छत्तीसगढ़ के विकास और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विमल चोपड़ा मोहन एंटी, रमेश सिंह ठाकुर, सुभाष तिवारी, मीनल चौबे महेश शर्मा,श्याम सुंदर अग्रवाल, मृत्युंजय दुबे, मुरली शर्मा, हरि बल्लभ अग्रवाल, रामकिंकर सिंह, सुनील शुक्ला, प्रशांत सिंह ठाकुर, पायल अंबानी, बबली सेन, सविता साहू, विश्वजीत साहू समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से भयभीत : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भूपेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से भयभीत भाजपा ने पहले भूपेश सरकार की योजनाओं का विरोध किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया, मोदी सरकार के माध्यम से अड़चन डालने का प्रयास किया और अब भाजपा कांग्रेस द्वारा की जा रही घोषणाओं का भी विरोध कर रही है और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के 9

भाजपा सांसद पूरे पांच साल मोदी सरकार के साथ मिलकर हर पल यह षड्यंत्र रचते रहे किस प्रकार से भूपेश सरकार की योजनाओं को रोका जाए। जब भूपेश सरकार ने किसानों को 2500 रु. समर्थन मूल्य देने की बात कही तब मोदी सरकार ने सेंट्रल पूल में चावल लेने से मना कर दिया, धान खरीदी के समय केंद्र सरकार बारदाने की आपूर्ति रोक देती है, कभी मोदी सरकार कहती है कि हम केंद्रीय पूल में उसना चावल नहीं लेंगे। भूपेश सरकार ने जब पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा की तो मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारीयों द्वारा जमा किया गया 17200 करोड़ देने से मना कर दिया। भूपेश सरकार की योजनाओं में रोड़े अटकाने और विरोध के साथ ही भाजपा ने उन जन कल्याणकारी कामों का विरोध करने और भ्रम फैलाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी ने छत्तीसगढ़ आकर बड़ी ही बेशर्मी से खुलेआम झूठ बोल दिया।

भाजपा का डबल इंजन यानी जनता के साथ डबल धोखा: ठाकुर

रायपुर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 2018 के पहले भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी लेकिन राम वन गमन पथ माता कौशल्या की मंदिर नही बनाए।भाजपा की डबल इंजन की सरकार यानी कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार,वादाखिलाफी धोखा,लूट झूठ और जुमला इसके अलावा कुछ नही है। भाजपा

की डबल इंजन की सरकार से जनता को डबल धोखा मिल रहा है। मोदी, योगी, मामा, और खट्टर ने जनता के भविष्य का भट्ठा बैठा दिया। डबल इंजन की सरकार ने परेशानियों में जनता से ताली घंटी दीया जलवाते रहे और देश प्रदेश की सम्पतियों को दो लोगो को माटी के मोल बेचकर चुना लगा रहे है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित भाजपा शासित राज्यों एवं केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव में जनता से किये वादों में से एक भी वादा को पूरा नहीं किया है सिर्फ धोखा दिया है जनता भाजपा की केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों से धोखा खायी है। डबल इंजन की सरकार जनता के भविष्य को कुचल रही है जनता के ऊपर डबल आफत बनकर टूट रही है किसान, नौजवान, माता, बहने, और बेटियों सबके लिए ट्रबल इंजन है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों को कर्ज मुक्त किया है, बिजली बिल हाफ दिया है, सिंचाई कर माफ किया है, आदिवासियों के कानूनी अधिकार दिए हैं।

जयराम की बातों को भाजपाई गलत प्रस्तुत कर रहे: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना एक और वायदा निभा दिया। छत्तीसगढ़ के किसानों की 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी प्रदेश भर में शुरू हो चुकी है। भाजपा धान खरीदी में रोक लगवाना चाहती है, उसने धान खरीदी बंद करने के लिये चुनाव आयोग में शिकायत किया है। प्रदेश

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान खरीदी पर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। धान खरीदी में केन्द्र का योगदान है। धान खरीदी में केन्द्र का योगदान केवल इतना ही है कि वह अन्य फसलों के समान धान का भी समर्थन मूल्य सिर्फ घोषित करता है। खरीदी राज्य सरकार करती है। जयराम रमेश ने उसी घोषित समर्थन मूल्य की बात कही है। मोदी सरकार का धान खरीदी में कोई योगदान नहीं है। धान खरीदी का पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार मार्कफेड के माध्यम से विभिन्न बैंको से कर्ज लेकर धान खरीदी करती है। किसानों को छत्तीसगढ़ में 2640 रूपये, देश ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत भूपेश सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी नेता भ्रम फैलाने के लिये जबरिया वाहवाही लेने के लिये राजनीति कर रहे है। पिछले वर्ष 107 लाख मीट्रिक धान की खरीदी कांग्रेस सरकार ने किया था। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

भूपेश सरकार ने 40 लाख को गरीबी से बाहर निकाला: वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार में विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के सभी वर्गो के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आए हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है। 15 साल के रमन सिंह के कुशासन में कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत, बेरोजगारी, गरीबी और बदहाली ही छत्तीसगढ़ की

पहचान बना दी गई थी, नक्सलवाद प्रदेश में चरम पर था। पिछले पांच वर्षों में भूपेश सरकार की योजनाओं के चलते छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। राज्य में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या में कमी आई है। प्रदेश के तीन जिलों कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 23 से 25 फीसदी लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह हम नहीं नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कह रही है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 13.53 फीसदी लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 2020 की प्रोजेक्टेड जनसंख्या में तो यह संख्या 39 लाख 90 हजार से ज्यादा है। जो भूपेश सरकार में घटकर 19.37 फीसदी रह गई।भूपेश सरकार में जो समृद्धि आई है उसका कारण भी स्पष्ट है प्रदेश के 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9 हजार और 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जा रही है।

लोककल्याण हैं जरुरी, लेकिन नक्सलवाद को नहीं किया जा सकता खत्म: टंडन

रायपुर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में द्वितीय कमान अधिकारी डा. विनोद कुमार टंडन ने अपने द्वारा लिखे नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयास और इस पर पुलिस प्रशासन की भूमिका और वर्तमान परिदृश्य पुस्तक का आज प्रेस क्लब में विमोचन किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में 1967 की विजयी

गाथा से लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ में 7 मई 2023 को अरणपुर में हुई घटना का जिक्र किया गया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी वहां कब्जा कर अलग देश की मांग करते हुए आए दिन कश्मीर के रहने वाले भाई-बहनों पर हमला कर रहे हैं और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में नक्सली व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर ग्रामीणों व जवानों पर हमला कर रहे है। नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से कभी खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन कुछ हद तक रोका जरुर जा सकता है, इसके लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन के साथ ही आम जनता को भी कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। नक्सली वे लोग बनते हैं जिनके पास राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं और वे निराश और हताश होकर माओवादियों के शरण में चले जाते है और वहीं से वे ट्रेनिंग लेकर नक्सली बनते हैं।

सुकमा की चुनावी सभा में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह पर बरसे भूपेश बघेल

रमन राज में हावी थी कमीशनखोरी: सीएम बघेल

रायपुर। सुकमा की जनसभा में भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दौर वो भी था जब भाजपा की सरकार थी और उन्होंने महुआ की खरीदी बंद कर दी, जिससे इतिहास में पहली बार आदिवासियों को महुआ को सड़क पर फेंकना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में आदिवासी सताये गए और उन्हें ठगा गया।

विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि डॉ रमन सिंह ने हमेशा झूठ

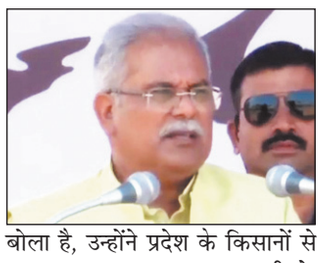

बोला है, उन्होंने प्रदेश के किसानों से धान का एक-एक दाना खरीदने, 2100 समर्थन मूल्य का दाम देने, आदिवासियों को जर्सी गाय देने, प्रत्येक आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी देने समेत कई वादे जनता से किए थे जिसे कभी पूरा नहीं किया। चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर एक बार पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह को कमीशनखोर बताते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ रमन सिंह कमीशनखोरी किए, चप्पल, मोबाइल और टिफिन बांटने में कमीशन खाया और भ्रष्टाचार किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार के दौरान नक्सल हमलों और सुरक्षा चूक के कारण हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज से 5 बरस पहले तक किसी काम से सुकमा आना पड़ता था तो 10 बार सोचना पड़ता था, खौफ ऐसा था कि हम जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते से वापस नहीं जाते थे। मुख्यमंत्री ने झीरम घाटी प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि जिस झीरम घाटी में हमारे नेताओं की शहादत हुई थी आज वहां रात के 10 बजे-12 बजे तक आ-जा सकते हैं।

5 साल में बदला सुकमा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल के दौरान कांग्रेस सरकार में हुए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि गांवों में सड़कें बनीं, राशन दुकानें खुली, 300 बंद स्कूल फिर से खुले, शिक्षा की व्यवस्था की, लाइब्रेरी खोली गई।

भाजपा की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति

रायपुर। राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और एआईसीसी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि ये चुनाव छत्तीसगढ़ में विधानसभा के लिये चुनाव है। ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये लोकसभा के लिये नहीं है। छत्तसीसगढ़ से संबंधित मुद्दों पर लड़ा जायेगा। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है जो हमारा चुनावी अभियान है, जो हमारी गारंटी है, हमारे वादे स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की जो चिंता है, छत्तीसगढ़ की जनता की जो उम्मीदें हैं उसको हम अपने अभियान के द्वारा दर्शा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है।

भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा मुद्दाविहीन पार्टी है।

विगत दिनों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, असम के मुख्यमंत्री भी आए है। उनके भाषणों में केवल एक ही मुद्दा है ध्रुवीकरण की। आपको याद होगा 16 तारीख को देश के गृहमंत्री छत्तीसगढ़ आये थे। 18 तारीख को असम के मुख्यमंत्री आये थे। उनके चुनावी भाषणों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम पेश किया है। हमने शिकायत की है, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने खुद गया था। उन्होंने नोटिस असम के मुख्यमंत्री को दिया है जो कवर्धा में उनका भाषण था। हालांकि गृहमंत्री के बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की, पर हम उम्मीद करते है कि गृह मंत्री के भाषण पर उनको जो कार्यवाही करनी है, वो करेंगे। ध्रुवीकरण के अलावा भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव के कुछ ही दिन बाकी है, उसके लिये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग-अलग मुख्यमंत्री आयेंगे केवल इसी भावना से आयेंगे की कैसे ध्रुवीकरण का प्रोत्साहन कर सकें। हम इसका मुकाबला करेंगे हम डरते नहीं है। ये जो चुनावी टक्कर है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.